फिर सड़क पर राहुल

इस हफ्ते

कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के जरिए राहुल गांधी के पास इन राज्यों में फिर से खड़ा होने का एक मौका है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल आमजन तक पहुंचने का प्रयास करते दिख रहे हैं। भाजपा शासनकाल के दौरान बेरोजगारी और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगा वह जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं

पृष्ठ 2

दि संडे पोस्ट

2001 से प्रकाशित

28 जनवरी से 03 फरवरी 2024, मूल्य : 3:00

हर रविवार को देहरादून से प्रकाशित

ना काहू से दोस्ती - ना काहू से बैर

वर्ष 15, अंक : 33, उत्तराखण्ड संस्करण (पृष्ठ 28)

वेबसाइट www.thesundaypost.in

महिलाएं उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की रीढ मानी जाती हैं। वे राज्य में लोकतंत्र की भी बुनियाद हैं। चुनाव-दर-चुनाव यहां महिलाओं की मतदान में हिस्सेदारी पुरुषों के उत्साह पर भारी पड़ती है। इसके मद्देनजर लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी आधी आबादी को साधने की कवायद में जुट गए हैं। अब तक आधा दर्जन जिलों में नारी शक्ति सम्मेलन कर चुके धामी महिला सशक्तिकरण का संदेश देने में कामयाब होते दिख रहे हैं। कहीं वह महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर सूत कातते नजर आए तो कहीं सिलबट्टे पर चटनी पिसते तो कहीं चक्की चलाकर महिलाओं का दिल जीत रहे हैं। रोड शो में भारी भीड़ और महिलाओं के बीच धामी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष हैरान-परेशान नजर आने लगा है तो वहीं राजनीतिक पंडितों का आकलन है कि 'मिशन शक्ति' के जरिए सीएम धामी भाजपा को बड़ा सियासी फायदा पहुंचा सकते हैं

आवरण-कथा

मिशन शक्ति

पृष्ठ 5

भारत जोड़ो न्याय यात्रा

फिर सड़क पर राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से सड़क पर हैं। 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के जरिए राहुल का लक्ष्य 15 राज्यों के 110 जिलों में पहुंचना है। मकर संक्रांति के दिन मणिपुर से शुरू हुई 66 दिन की इस यात्रा के दौरान राहुल 6,200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, नागालैंड, असम और मेघालय से होते हुए यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से गुजरते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र में समाप्त होगी। कांग्रेस 'न्याय का हक मिलने तक' का नारा दे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इस यात्रा के जरिए घेरने की रणनीति पर काम कर रही है तो भाजपा राहुल की इस यात्रा को चुनावी नौटंकी कह मोदी के नेतृत्व में असली न्याय जनता तक पहुंचाने का दावा कर रही है

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

सात सितंबर, २०२२ को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में राहुल गांधी ने अपनी 'भारत जोड़ो' यात्रा का आगाज किया था। १३६ दिनों तक चली इस पद यात्रा के दौरान राहुल ने ६७१३ किलोमीटर का सफर ६६ दिनों में पूरा कर एक रिकॉर्ड स्थापित करने का काम तो किया ही था, कांग्रेस संगठन में भी इस यात्रा ने नई स्फूर्ति तब पैदा की थी। 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल ने भाजपा शासनकाल के दौरान कथित तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों में आ रही गिरावट, बेरोजगारी तथा धर्म के नाम पर समाज को बांटने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित किया था। यह यात्रा ३० जनवरी, २०२३ को श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में 'महंगाई से नाता जोड़ो, मिलकर भारत जोड़ा और 'नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो' जैसे नारों के साथ समाप्त हुई थी। इस यात्रा के ठीक एक बरस बाद और लोकसभा चुनाव २०२४ से ठीक पहले राहुल का दोबारा यात्रा पर निकलना भाजपा के लिए चिंता का बायस तो कांग्रेस के मृतप्राय संगठन में जान फूंकने की कवायद बतौर देखा जा रहा है।

राहुल की रणनीति

राजनीतिक विश्लेषकों की राय में राहुल और कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए ३५५ लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का है। इनमें से वर्तमान में भाजपा के पास २३६ सीटें हैं जबकि कांग्रेस २०१९ में मात्र १४ सीटें जीत पाई थीं। कांग्रेस रणनीतिकारों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के मुद्दों पर वह संवेदनशील है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मणिपुर में चल रहे जातीय तनाव को नजरअंदाज करने का पुरजोर विरोध करती है। राहुल की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम मची है। हिंदी पट्टी के राज्य विशेष रूप से पूरी तरह राममय हो चले हैं। यह स्पष्ट है कि भाजपा की रणनीति २०२४ के लोकसभा चुनाव में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण पर केंद्रित है। ऐसे में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए भाजपा के पक्ष में बने माहौल की धार कुंद करने का प्रयास कर रही है।

शुरुआती चरण में सफलता

राहुल गांधी की यात्रा का मणिपुर में खासा प्रभाव रहा। जहां-जहां से यात्रा गुजरी, उन्हें सुनने और देखने के लिए भारी जनसमूह मौजूद रहा। इससे कांग्रेस भीतर उत्साह का संचार देखने को मिल रहा है। असम में प्रवेश करते ही राहुल के तेवर भाजपा के खिलाफ बेहद आक्रमक हो गए। १८ जनवरी को सिवालनगर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं संग संवाद के दौरान राहुल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला बोलते हुए असम सरकार को देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार का तमगा दे डाला। बकौल राहुल 'असम सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। हम यात्रा के दौरान इस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करेंगे।' पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से तिलमिलाए हेमंत बिस्वा शर्मा ने गांधी परिवार पर व्यक्तिगत् हमला करते हुए उसे भ्रष्ट परिवार कह पुकारा। बिस्वा ने यात्रा को धार्मिक रंग देने का काम भी कर दिखाया। बकौल बिसवा यह यात्रा 'न्याय यात्रा' नहीं, बल्कि 'मियां यात्रा' है। असम में भी यात्रा को भारी जनसमर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस बीच जोहर जिला पुलिस ने इस यात्रा पर तयशुदा मार्ग से अलग चलने और यातायात नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए यात्रा के आयोजकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमें पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि 'असम के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। भारत जोड़ों न्याय यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है। हिमंत बिस्वा सरमा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग सड़क पर न आएं और राहुल गांधी को न देख पाएं। उन्हें जो कुछ करना है, करने दीजिए। हमें जो कुछ करना है, वो हम करेंगे।'

भाजपा समर्थकों का यात्रा पर हमला

'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के काफिले पर असम के सोनितपुर जिले में भाजपा समर्थकों के हमले का समाचार हालांकि राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां नहीं बना लेकिन कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाती नजर आ रही है। इस हमले के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चोटिल हो गए और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लि कार्जुन खड़गे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को इस हमले के लिए सीधे जिम्मेवार बताते हुए कहा है कि असम की सत्तारूढ़ भाजपा इस न्याय यात्रा से इतनी डरी हुई है कि उसने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा पर हमला तक कर दिया। खड़गे का कहना है कि गत् वर्ष 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान कहीं भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी लेकिन न्याय यात्रा से हेमंत बिस्वा सरकार डर गई है।

मंदिर प्रवेश पर रोक

२२ जनवरी को असम पुलिस ने राहुल गांधी को छईबोरा गांव स्थित श्रीश्री शंकर देव मंदिर में प्रवेश करने से रोक एक नए विवाद को जन्म दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें मंदिर ट्रस्ट द्वारा आमंत्रण दिया गया था लेकिन हेमंत बिस्वा सरमा के आदेश पर राहुल गांधी को सुबह मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। राहुल गांधी इसके बाद काफी देर तक मंदिर के बाहर धरने पर बैठे रहे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से यह कहकर खारिज कर दिया कि राहुल गांधी को पूर्व में ही सूचित कर दिया गया था कि वे ३ बजे के बाद दर्शन करने आएं।

उत्तर भारत पर फोकस

राहुल की यह यात्रा मध्य प्रदेश में सात दिनों के भीतर ६९८ किलोमीटर का सफर तय करेगी और सात जिलों से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश में गत् विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद प्रदेश कांग्रेस का संगठन खासा हतोउत्साहित है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए राहुल पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने का काम करेंगे। यह यात्रा सबसे अधिक ११ दिन उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। इस दौरान प्रदेश के २० जनपदों को १०७४ किलोमीटर की दूरी तय कर कवर किया जाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा में सबसे अधिक सांसद उत्तर प्रदेश ही भेजता है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा उत्तर प्रदेश आज पूरी तरह से भगवामयी हो चुका है और कांग्रेस का जमीनी आधार पूरी तरह समाप्त हो चला है। २०१९ के आम चुनाव में पार्टी मात्र एक सीट राय बरेली जीत पाने में सफल रही थी। स्वयं राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी से चुनाव हाए गए थे।

28 जनवरी से 03 फरवरी 2024 तक के लिए प्रकाशित

संपादक : अपूर्व* कार्यकारी संपादक (विचार) : आदेश भाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सुनील भारद्वाज, रोविंग एसोसिएट एडिटर : आकाश नागर
उप संपादक : जीवन सिंह टनवाल, जनार्दन कुमार सिंह, मो. रुस्तम उत्तराखण्ड प्रभारी : दिव्य सिंह रावत, विशेष संवाददाता : कृष्ण कुमार, मुख्य संवाददाता
कुमाऊं : संजय स्वार, संवाददाता : दिनेश पंत, गोपाल बोरा, गढ़वाल संवाददाता : जसपाल नेगी, अली खान, प्रबंधक : अमित कुमार : 9582371321 **प्रधान कार्यालय :** बी-107, सेक्टर-63, नोएडा, फोन : 0120-4330755, फैक्स : 0120-4352397,
उत्तराखण्ड कार्यालय : रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून, मो. : 09412901406 **कुमाऊं कार्यालय :** प्रथम तल, नंदा इंक्लेव, नरसिंह तल्ला, कमलवागंज रोड हल्द्वानी-263139, नैनीताल।
* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी। स्वत्वाधिकारी इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसायटी के लिए प्रकाशक, मुद्रक नारायण सिंह राणा द्वारा बी.एफ.एल. इन्फोटेक लि., सी-9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित एवं 3, रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून से प्रकाशित।

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 03 फरवरी, 2024

अपने-अपने राम

लबरेज़ है शराब-ए-हक़ीक़त से जाम-ए-हिंद
सब फ़लसफ़ी हैं खित्ता-ए-मग़रिब के राम-ए-हिंद

ये हिन्दियों की फ़िक्र-ए-फ़लक-रस का है असर
रिफ़अत में आसमां से भी ऊंचा है बाम-ए-हिंद

इस देस में हुए हैं हज़ारों मलक-सरिश्त

मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम-ए-हिंद
है राम के वजूद पे हिन्दोस्तां को नाज़

अहल-ए-नज़र समझते हैं इस को इमाम-ए-हिंद
एजाज़ इस चराग़-ए-हिदायत का है यही

रोशन-तर-अज़-सहर है ज़माने में शाम-ए-हिंद
तलवार का धनी था शुजाअ'त में फ़र्द था
पाकीज़गी में जोश-ए-मोहब्बत में फ़र्द था

-अल्लामा इकबाल

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वह कर पाने में बेहद सफल रही है जो सौ वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी नहीं कर पाया। 22 जनवरी और उसके पहले के एक पखवाड़े में अद्भुत-अद्वितीय इवेंट मैनेजमेंट भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने बखूबी आयोजित कर उनके लिए भी राम को अनिवार्य बना डाला जो खुद को पंथ निरपेक्ष कहलाने का दावा करते रहे हैं। यह मामूली बात नहीं हैं, यह नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हिंदू नेता बनने का प्रमाण है कि करोड़ों आम भारतीयों से लेकर कारपोरेट के दिग्गज, देश का मीडिया और कथित धर्मनिरपेक्ष राजनेता, सभी राममय हो चले हैं। फिर चाहे समाजवादी अखिलेश यादव हों या फिर पंथनिरपेक्षता का दावा करने वाले राहुल गांधी, हरेक खुद को राम भक्त प्रमाणित करने का प्रयास करता नज़र आ रहा है। इकबाल ने राम को भले ही अलग अर्थों में 'इमाम-ए-हिंद' कह पुकारा हो, वर्तमान में राम अनिवार्य बन चुके हैं

बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे देश, विशेषकर उत्तर भारत में इन दिनों राममय माहौल है। ऐसा महसूस हो रहा है कि दशकों का वनवास काट अब कलयुग में ही भगवान राम की घर वापसी हो पाई है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में एक धर्म विशेष के आराध्य की मूर्ति के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम अवसर पर संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठी सरकारों ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जाहिर है अब धर्मनिरपेक्षता के अर्थ, उसके मायने पूरी तरह बदल गए हैं। बहुसंख्यक को जो सुहाता हो उसे ही सत्य मान लेना आज के भारत का सच है। जो इस आज के सच से इत्तेफाक न रखता हो, वह देशभक्त कहलाने का हकदार नहीं है। बहरहाल ऐसे सर्द समय में मुझे अल्लामा इकबाल की उपरोक्त नज़्म याद हो आई। मेरे लिए इस नज़्म में वर्णित राम ही असली राम है। ऐसे राम जिन्होंने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे राम जो राज परिवार में जन्मे जरूर लेकिन तमाम ऐश्वर्य को दरकिनार कर जिन्होंने दलितों, वंचितों, आदिवासियों, महिलाओं के दर्द को समझने और उसका निवारण करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहां हर रोज सुबह और शाम विधिवत पूजा-अर्चना की जाती थी। मेरे पिता शिव के परम्भक्त थे। उनकी भक्ति लेकिन उनकी निजी आस्था और विश्वास का प्रतीक थी। दूसरे धर्मों का सम्मान करना उनके हिंदू होने का धर्म था। ऐसे माहौल में परवरिश का असर है कि मैं हरेक धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपने धर्म का। मेरे लिए भी ईश्वर निजी आस्था का विषय है। इसलिए इस चौतरफा राममय माहौल में मैं स्वयं को बेहद असहज महसूस रहा हूं। इतिहास में कई बार ऐसे क्षण, ऐसा वक्त आता है जब तमाम तर्क, मर्यादाएं और मानवीय सरोकार धरे के धरे रह जाते हैं, केवल और केवल उन्माद की सत्ता स्थापित हो जाती है। मेरी दृष्टि में वर्तमान समय ऐसा ही है। भगवान राम के नाम पर सनातन धर्म को बाकी धर्मों से श्रेष्ठ बताया जा रहा है। निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वह कर पाने में बेहद सफल रही है जो सौ वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी नहीं कर पाया। २२ जनवरी और उसके पहले के एक पखवाड़े में अद्भुत-अद्वितीय इवेंट मैनेजमेंट भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने बखूबी आयोजित कर उनके लिए भी राम को अनिवार्य बना डाला जो खुद को पंथ निरपेक्ष कहलाने का दावा करते रहे हैं। यह मामूली बात नहीं हैं, यह नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हिंदू नेता बनने का प्रमाण है कि करोड़ों आम भारतीयों से लेकर कारपोरेट के दिग्गज, देश का मीडिया और कथित धर्मनिरपेक्ष राजनेता, सभी राममय हो चले हैं। फिर चाहे समाजवादी अखिलेश यादव हों या फिर पंथनिरपेक्षता का दावा करने वाले राहुल गांधी, हरेक खुद को राम भक्त प्रमाणित करने का प्रयास करता नज़र आ रहा है। इकबाल ने राम को भले ही अलग अर्थों में 'इमाम-ए-हिंद' कह पुकारा हो, वर्तमान में राम अनिवार्य बन चुके हैं। हालात यह है कि यदि आप राम की अवधारणा से सहमत न भी हों तो भी आप संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी का वास्ता दे अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। फिर भी यदि आप दुस्साहस करते हैं तो आपको देशद्रोही तक करार दिया जा सकता है। यही कारण है कि हर कीमत पर राजसत्ता पाने को आतुर हमारे कथित धर्मनिरपेक्ष राजनेता भी किसी न किसी प्रकार से खुद को रामभक्त साबित करने में जुटे हैं। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश ने २२ जनवरी को राजकीय अवकाश इसी नीयत और मजबूरी से किया तो राहुल और अखिलेश भी रामलला के दर्शन करने जाने की बात कह रहे हैं। भगवत गीता के १७वें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि -

सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम।।

अर्थात जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक देने वाला राजसी (राजोगुणी) तप कहा जाता है।

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि इसी प्रकार का राजसी तप है जिसका फल स्थाई नहीं क्षणिक है। लेकिन वर्तमान का सबसे बड़ा संकट यही है कि तर्क को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तार्किकता एक प्रकार का अभिशाप बन चुकी है। मुझे लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं कि मेरे राम गली-मोहल्लों में टंगे भगवा ध्वज वाले राम कतई नहीं हैं। मेरे राम भोग के नहीं, बल्कि त्याग के प्रतीक हैं। वे क्रोध के नहीं, करुणा के महासागर हैं। राम मेरे लिए मर्यादा के शिखर पुरुष हैं जिन्हें किसी मंदिर की चारदिवारी तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। राम को पाना है तो गरीबों-वंचितों के आंसुओं को पोछने का काम करना होगा। राम भक्ति नारों में नहीं मिल सकती है, न ही खरबों खर्च कर बने मंदिर में उनके दर्शन हो सकते हैं। राम को पाने का सबसे सरल लेकिन उतना ही कठिन मार्ग है मर्यादित जीवन जीने का, अपने वचनों को निभाने का, अहिल्या सरीखी पीड़िताओं के रक्षक बनने का, शबरी के जूठे बेरों को खाने की करुणा रखने का। मेरे राम तो यही राम हैं। इसलिए इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन मैंने खुद को असहज महसूसा। मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदू परिवार में जन्मा। मुझसे पूछा नहीं गया था लेकिन यदि मुझसे यह पूछा जाए कि मैं अगला जन्म किस धर्म में लेना चाहूंगा तो मैं निःसंकोच कह दूंगा हिंदू धर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा धर्म सहिष्णुता सिखाता है, वह मुझे करुणामयी बनने की शिक्षा देता है। मेरा धर्म किसी एक पुस्तक में दी गई हिदायतों से नहीं बंधा है। वह इतनी विराट सोच वाला है कि खुद अपनी पुस्तकों में वह अपने ही भगवान के अवतारों तक को उनकी गलतियों के लिए दंडित करने की शक्ति रखता है। यह धर्म मुझे जीवन और मृत्यु के परे ले जाता है। कोई दूसरा धर्म नहीं जो मुक्ति का ऐसा मार्ग बताता हो। इतने विराट धर्म का उपासक होने के कारण मुझे समदर्शी होने की दृष्टि मिली है। यह दृष्टि ही मुझे बेचैन कर रही है क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि वर्तमान समय में छद्म हिंदुत्व चारों तरफ छा गया है।

राम रघुकुल से आते हैं। उस रघुकुल से जिसकी रीत है-प्राण जाई पर वचन जाई। कोई याद रखना नहीं चाहता, न ही कोई याद दिलाना चाहता है कि राम को अपना आराध्य मानने वाले भाजपा नेता कल्याण सिंह ने १९९२ में बतौर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट को यह वचन दिया था कि विवादित ढांचे की हर कीमत रक्षा की जाएगी। लेकिन ६ दिसंबर को इस वचन का पालन नहीं किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि राम की तरह मर्यादित जीवन कोई नहीं जीना चाहता है। भगवान राम का पूरा जीवन वचन निभाने में बीता। उन्होंने विषम परिस्थिति में भी विवेक के साथ मर्यादा की स्थापना और रक्षा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की मूर्ति के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम बाद दिए अपने वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि काम का चरित्र न तो संकीर्णता सिखाता है और न संघर्ष। उन्होंने कहा कि राम ऊर्जा हैं आग नहीं, वह समाधान हैं, विवाद नहीं। मैं पूरी तरह अपने प्रधानमंत्री के इस कथन से सहमति रखता हूं। भगवान राम का पूरा जीवन दर्शन विवाद पर नहीं, बल्कि सर्वमान्य समाधान की बात करता है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद अब एक हजार साल के भारत की नींव रखने का आह्वान देशवासियों से किया है। उन्होंने देशवासियों से अपनी चेतना को विस्तार देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि चेतना का विस्तार देव से देश और राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा उसका पालन देशवासियों के साथ-साथ उनकी पार्टी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना पाले अन्य सभी संगठन भी करेंगे। हालांकि ऐसा होता मुझे संभव नहीं लगता है।

कहा जाता है कि वेदव्यास पूरी महाभारत लिखने के पश्चात बेहद निराश हो उठे थे। तब उन्होंने कहा था 'मैं हाथ-ऊंचा उठाकर पुकार रहा हूं लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। धर्म का पालन करने से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों सधते हैं लेकिन धर्म का पालन कोई नहीं करता।' आज भी हालात ठीक वैसे ही हैं। पूरा देश राममय जरूर है लेकिन भगवान राम की तरह मर्यादित कोई नहीं।

सरगोशियां

किनारा करेंगे कटारिया!

राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री रह चुके लालचंद कटारिया को लेकर पिछले दिनों चर्चा थी कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसको लेकर अब सियासी संकेत भी सामने आने लगे हैं। लालचंद कटारिया का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात का एक फोटो सामने आया है जिसके बाद एक बार फिर चर्चा जोरों पर है कि कटारिया बीजेपी का दामन पकड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति से कटारिया की मुलाकात को इसी संकेत से जोड़कर देखा जा रहा है। लालचंद कटारिया का निर्वाचन क्षेत्र झोटवाड़ा विधानसभा था। लेकिन इस बार उनके क्षेत्र में उनका काफी विरोध रहा। उसको देखते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और यह तर्क दिया कि वह राजनीति की जगह अध्यात्म की ओर ध्यान देंगे। तब कटारिया ने कहा कि न तो वे खुद चुनाव लड़ेंगे और न ही उनका कोई करीबी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इसी तरह वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। मगर बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के साथ उनकी मुलाकात के बाद कुछ और ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान आरएसएस से जुड़े हुए पदाधिकारी भी मौजूद थे जो नए रणनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। कटारिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं।

सिरसा से चुनाव लड़ेंगे तंवर

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का समय शेष है लेकिन नेताओं का दलबदल अभी से शुरू हो गया है। आया राम-गयाराम की राजनीति वाले प्रदेश हरियाणा में पैर जमाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 'आप' के चुनाव अभियान कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे भाजपा में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में सिरसा से मैदान में उतार सकती है। गौरतलब है कि अशोक तंवर ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। जब अशोक तंवर कांग्रेस में थे तो उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद माना जा रहा था कि वे हरियाणा में अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अप्रैल २०२२ में उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना लिया था। उसके बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हरियाणा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में जब कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है तो उनका पार्टी को छोड़ना आप को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। साल के शुरुआत में ही पार्टी की हरियाणा इकाई की उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा अपने पिता निर्मल सिंह के साथ कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं। इस तरह से अब तंवर के जाने से पार्टी को यह दूसरा झटका लगा है जो आगे भी देखने को मिल सकता है।

दल बदल सकते हैं दानिश

हाल ही में बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए दानिश अली एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर कहा कि 'ये फैसला मेरे लिए एक बहुत ही अहम है। इसे मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। कांग्रेस की यात्रा में इसलिए शामिल हो रहा हूं, क्योंकि यह अन्याय के खिलाफ आंदोलन है। न्याय के लिए लड़ना गलत बात नहीं है।' दानिश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जिस समय देश की सत्ताधारी दल के नेता ने उन पर संसद में टिप्पणी की थी उस समय मुझे और मेरे परिवार को हौसला देने वाले राहुल गांधी ही देश के पहले नेता थे। उनके इस पोस्ट के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि मैं बसपा का सिपाही हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ कांग्रेस की इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। अमरोहा से सांसद दानिश अली अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी भाजपाइयों से नोक-झोंक का मामला हो या फिर संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा की टिप्पणी का मामला। पिछले दिनों बसपा ने दाशिन अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लगातार राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात इस बात की ओर इशारा कर रही थी। अब दानिश अली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के ऐलान के बाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं।

कितनी कारगर होगी मंदिर राजनीति?

फोटो : इंडिया टीवी हिंदी पोर्टल से

दि संडे पोस्ट डेस्क

इन दिनों देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आगामी आम चुनाव २०२४ को फतह करने की भरसक कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर हैं, वहीं भाजपा ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा का जिस तरह से आयोजन किया उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।

कहा जा रहा है कि आम चुनाव से ठीक पहले मंदिर की राजनीति के जरिए भाजपा इंडिया गठबंधन को घेरना चाहती है। वैसे भी कई विपक्षी दलों ने कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। ऐसे में बीजेपी काफी आसानी से उन्हें हिंदू विरोधी बात कर एक विशेष वर्ग को अपने पाले में करना चाहती है। ऐसे में सवाल है कि राम आएंगे, क्या वोट दिलाएंगे? भाजपा को इसका कितना फायदा होगा? क्या भाजपा को आसानी से लोकसभा चुनाव में जीत मिल जाएगी? कितनी कारगर होगी मंदिर की राजनीति?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतना सरल भी नहीं है यह गणित। भाजपा के लिए कई चुनौतियां भी हैं। बीजेपी मंदिर पॉलिटिक्स की राह पर जरूर चलती है, लेकिन उसका ये मानकर चलना कि इसी राम मंदिर के जरिए उसे ४०० से अधिक सीटें मिल जाएंगी, ये गलत है। नेरेटिव अपनी जगह है लेकिन जो तथ्य हैं, वो कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि हिंदी पट्टी राज्यों में भाजपा विपक्ष के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में है।

बात चाहे २०१४ के चुनाव की हो या फिर २०१९ के लोकसभा चुनाव की, पार्टी ने हिंदी भाषी राज्यों में एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। अगर हिंदी पट्टी राज्यों के साथ दक्षिण के कर्नाटक को भी जोड़ लिया जाए तो बीजेपी ने २०१९ के चुनाव में २११ सीटें अपने नाम की थी। २०१४ में ये आंकड़ा २१० सीटों का था। लेकिन बड़ा खेल ये रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर १२ प्रतिशत के करीब बढ़ गया, मगर सीटों में बढ़ोतरी सिर्फ एक रही। अब यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता भी है, उसे भी इस बात का एहसास है कि बढ़े हुए वोट बैंक का मतलब ये नहीं कि सीटों में भी उतना ही इजाफा हो जाएगा।

सियासी जानकार तो यहां कह रहे हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने पिछले दो चुनावों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है, यानी कि सुधार की गुंजाइश न के बराबर चल रही है। वहीं दूसरी बात ये है कि मंदिर की राजनीति का सबसे ज्यादा असर भी इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों में दिखता है। ऐसे में बीजेपी को किस तरह से इस हिंदुत्व की राजनीति से फायदा मिलेगा, इसका जवाब अभी देना मुश्किल है। बीजेपी को ये समझना भी जरूरी है कि वो उत्तर प्रदेश में ८० की ८० सीटें जीतने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत और वोटिंग पैटर्न उसके लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

असल में २०१९ के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में ८ फीसदी के करीब वोट शेयर बढ़ा था। उसने ५० फीसदी का बेंचमार्क छू लिया था, लेकिन हैरानी इस बात की रही कि इस प्रचंड वोट शेयर के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को २०१४ की तुलना में ९ सीटों का नुकसान हुआ।

बीजेपी समर्थकों की मानें तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए दक्षिण की राजनीति को भी पार्टी साधने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं और अलग-अलग मंदिरों का दौरा किया जा रहा है, रणनीति साफ पता चल रही है। लेकिन यहां भी आंकड़ों वाली हकीकत बीजेपी की राह को मुश्किल कर रही है। दक्षिण से कुल १३० सीटें लोकसभा की निकलती है, पिछली बार बीजेपी को इन्हीं १३० सीटों में से मात्र २९ पर संतुष्ट करना पड़ गया था। वहां भी कर्नाटक से ही उसे अकेले २५ सीटें मिली थीं।

इस बार बीजेपी तमिलनाडु में कुछ सीटें जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी की राजनीति और तमिलनाडु का सियासी मिजाज कभी भी मेल नहीं खाता है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में या केरल में धर्म के लिए कोई जगह नहीं, वहां भी कई मंदिर हैं, वहां पर हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन जिस तरह से धर्म की राजनीति को उत्तर भारत में तवज्जो दी जाती है, वैसा हाल तमिलनाडु या फिर केरल में देखने को नहीं मिलता है। बात अगर अकेले तमिलनाडु की हो तो वहां पर जिस तरह से कई सामाजिक आंदोलन चलाए गए, जिस तरह से द्रविड़ आंदोलन को धार दी गई उसने भी वहां के लोगों के लिए धर्म वाली राजनीति को कम सक्रिय कर दिया था। इसी वजह से बीजेपी जब भी तमिलनाडु में मंदिर पॉलिटिक्स का जिक्र करती है या फिर हिंदुत्व वाली राजनीति के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करती है, वहां की जनता उसे नकार देती है। ऐसे में मंदिर पॉलिटिक्स के जरिए इस बार दक्षिण में पार्टी कितना बड़ा उलटफेर कर पाएगी, इसे लेकर जानकारों के मन में ही कई प्रकार के संशय है।

बीजेपी में शामिल होंगी शर्मिष्ठा?

आगामी आम चुनाव को लेकर पार्टियों में नेताओं की एक दूसरी पार्टियों में आवागमन का खेल शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि वे चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो सकती हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अपनी पुस्तक 'प्रणब माई फादर, एडीटर रिमेम्बर्स' भी भेंट की। इस पुस्तक के लोकार्पण पर भी काफी बवाल हुआ था। इस पुस्तक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। शर्मिष्ठा ने पुस्तक में पिता प्रणब मुखर्जी की एक बात का जिक्र करते हुए दावा किया था कि वो राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता मानते थे और उनकी कई विषयों पर पकड़ कमजोर है। शर्मिष्ठा मुखर्जी नृत्यांगना होने के साथ-साथ अच्छी लेखक भी है। प्राथमिक सदस्य उन्होंने २०१४ में कांग्रेस का हाथ थाम २०१५ में कांग्रेस के सिंबल पर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन वे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज से चुनाव हार गई। इसके बाद शर्मिष्ठा ने २०२१ में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था लेकिन वे कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्य बनी रही। उनके भाई अभिजीत कांग्रेस पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शर्मिष्ठा बीजेपी में शामिल होंगी?

धामी का 'मिशन शक्ति'

आकाश नागर
akash@thesundaypostèin

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा के पूंजी निवेश करार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के सफलतम मुख्यमंत्रियों में शुमार हो चले हैं। इससे उत्साहित मुख्यमंत्री धामी अब मिशन 2024 के लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश में सामाजिक से लेकर आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाली महिला शक्ति को साधने के लिए वे जनसंपर्क अभियान पर हैं। अब तक आधा दर्जन जिलों में नारी शक्ति सम्मेलन कर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने में धामी कामयाब होते दिख रहे हैं। कहीं वे महिलाओं के साथ सूत कातते नजर आते हैं तो कहीं सिलबट्टे पर चटनी पिसते दिखते हैं। वे कहीं महिलाओं के साथ जमीन पर बैठे तो कहीं उन्होंने चक्की चलाकर महिलाओं का दिल जीत लिया। रोड शो में भारी भीड़ और महिलाओं के बीच धामी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष हैरान-परेशान नजर आने लगा है

ईजा-बैणी महोत्सव

दिनांक 30 नवंबर 2023 (स्थान-हल्द्वानी नैनीताल)

713 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, 30 हजार महिलाओं की मौजूदगी से मुख्यमंत्री धामी को मिला भारी समर्थन।

बेटी ब्वारियूंक कौथिक

दिनांक 28 दिसंबर 2023 (स्थान-नई टिहरी)

413 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी का अवलोकन करते समय सीएम धामी महिला उद्यमी के साथ जमीन पर ही बैठ गए और अपने हाथों से चक्की चलाने लगे। महिलाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उनकी मदद की और अपने हाथों से टोकरी भी बनाई।

चैली-ब्वारियूंक कौथिक

दिनांक 1 जनवरी 2024 (स्थान-कपकोट बागेश्वर)

100 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण। सीएम धामी ने की नववर्ष की शुरुआत, मातृशक्ति के साथ। महिलाओं के साथ बैठकर तांबे के बर्तनों में कला-कृतियों एवं रिंगाल की टोकरियां बनाई।

दीदी-बैणी नारी शक्ति महोत्सव

दिनांक 8 जनवरी 2024 (स्थान-उत्तरकाशी)

291 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण।

मुख्यमंत्री धामी ने नेशन अवार्ड में देश में दूसरे स्थान का सम्मान पाने वाले लाल धान के च्यूड़ा बनाने की जानकारी ली। महिला किसानों ने उन्हें लाल धान की बाली भेंट की। मुख्यमंत्री ने गिंज्याली (मूसल) थामकर पारंपरिक ओखली में महिलाओं के साथ लाल धान की कुटाई की। डुंडा और बगोरी क्षेत्र के पारंपरिक ऊन उत्पादकों से भेंटकर ऊन बुनाई व कताई के बारे में जानकारी ली और चरखा भी चलाया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने ऊन की कताई कर पारंपरिक ऊनी वस्त्रों को बढ़ावा देने का संदेश दिया।

नारी शक्ति वंदन महोत्सव

दिनांक 10 जनवरी 2024 (स्थान-रूद्रपुर)

मुख्यमंत्री ने चरखा में कताई कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। तुलसीमाला स्टॉल पर महिलाओं की इस स्वरोजगारपरक गतिविधि की सराहना करते हुए स्वयं भी इस पर अपना हाथ आजमाया और उन्हें इस कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। कन्याओं का पूजन कर प्रदेश की सुख-शांति, खुशहाली और चहुमुखी विकास की कामना की।

दीदी-बैणी नारी शक्ति महोत्सव

दिनांक 17 जनवरी 2024 (स्थान-पिथौरागढ़)

217.28 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री धामी ने धारचूला की दारमा, व्यास घाटियों के वाइब्रेंट विलेज से आई महिलाओं के साथ बागेश्वरी चरखे, तकली से ऊन कताई और रांच में पारंपरिक विधि से कालीन निर्माण का अनुभव लिया। साथ ही फिरका और बिंडा (मटका) के माध्यम से मट्ठा भी बनाया और सिलबट्टे में पहाड़ का पारंपरिक हरा नून (नमक) भी पीसा।

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में साढ़े तीन लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन कराने की सफलता के बाद सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सड़कों पर उतर जनता, खासकर महिलाओं को उनके सशक्तिकरण की बात कह लुभाने में जुट गए हैं। अब तक आधा दर्जन जिलों में नारी शक्ति सम्मेलन कर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने में कामयाब हो चुके हैं। इन महोत्सवों में धामी को महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ऐसे में जब खांचों में बंटा विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया में सक्रिय होकर अपने विपक्ष धर्म की इतिश्री कर रहा है। तब सीएम धामी ने सीधे जनता के बीच पहुंचकर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। चाहे कपकोट-बागेश्वर में रोड शो रहा हो या फिर हल्द्वानी, उत्तरकाशी या ऊधमसिंह नगर में महिला सम्मेलनों का आयोजन, भारी-भीड़ का उमड़ना बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है। 'नारी शक्ति वंदन महोत्सव' के जरिए सीएम धामी आधी आबादी को साधने का सियासी दांव-पेंच चल रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का आकलन है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह सक्रियता भाजपा को बड़ा सियासी फायदा पहुंचा सकती है।

> हम यत्र नारयस्तू पूजयन्ते तत्र रमयन्ते देवता वाले देश के गौरवशाली नागरिक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन में हमारी सरकार मातृ शक्ति के सशक्तिकरण का हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे आराध्य भगवान श्रीराम का पूरा जीवन दर्शन महिलाओं, दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने का रहा है। हम उसी दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं।
>
> ***पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड***

भाजपा की प्रदेश के युवा और महिला वोट बैंक पर खास नजर है। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 81.67 लाख मतदाताओं में से 39.31 लाख महिला मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में से सबसे अधिक करीब 22.34 लाख वोटर 30-39 आयु वर्ग के हैं। भाजपा का फोकस इन वोटों को साधने पर है। महिलाओं को आरक्षण का कानूनी अधिकार उत्तराखण्ड में धामी सरकार पहले ही दे चुकी है। इसमें महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दे दिया गया है।

पिथौरागढ़ की अधिवक्ता **अनीता पंत** मुख्यमंत्री के महिलाओं को समर्पित सम्मेलनों को सरकार के प्रति सकारात्मक रुझान बताती हैं और कहती हैं कि राज्य गठन में महिला शक्ति ही थी जिसने राज्य आंदोलन को गति देने का काम करते हुए बेहद अहम भूमिका निभाई। आज भी प्रदेश में तकरीबन पचास फीसदी महिला वोटर हैं। ऐसे में सरकार गठन में महिलाओं की भूमिका की महत्ता को मुख्यमंत्री धामी बखूबी समझ रहे हैं। महिलाओं के बीच जाकर वह उनके लिए नई-नई योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। इससे प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर महिला शक्ति मजबूत हो रही है।

दिनेशपुर (ऊधमसिंह नगर) की समाज सेविका **हीरा सिंह जंगपांगी** कहती हैं कि उत्तराखण्ड में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम को याद कीजिए जब महिलाएं पुरुषों से एक कदम आगे बढ़कर वोटिंग के लिए बाहर निकलीं और बम्पर मतदान किया था। जिसका नतीजा तमाम मिथकों को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता में वापसी कर इतिहास बना डाला। मुख्यमंत्री अब आधी आबादी की इस शक्ति को हाथ से नहीं खिसकने देना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए तीस फीसदी क्षैतिज आरक्षण के बाद अब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला नीति भी बनाने का फैसला कर लिया है। महिला नीति के इस शुरुआती ड्राफ्ट में पंचायतों में पचास प्रतिशत आरक्षण की तरह ही निकायों, निगमों में भी आरक्षण देने की बात कही है। इसके साथ ही पहाड़, भावर और तराई की राज्य की भौगोलिक सरंचना के अनुरूप महिलाओं के लिए सुरक्षा और सामाजिक हिस्सेदारी की बात भी इस नीति में रखी गई है। मुख्यमंत्री धामी इस सच से पूरी तरह वाकिफ हैं कि महिलाओं का वोट पाना है तो उनके उत्थान के लिए सोचना भी होगा। इसी रणनीति पर वह आगे बढ़ते दिख रहे हैं।

अल्मोड़ा की छात्रा और सोच संस्था की सक्रिय सदस्य **दीपिका पुनेठा** के अनुसार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ही 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम पास किया गया है। प्रदेश में धामी सरकार लखपती दीदी, नंदा गौरा, महिला पोषण अभियान समेत तमाम योजनाएं चलाकर महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है। 'नारी शक्ति वंदन महोत्सव' के जरिए सीएम धामी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं जिससे ये महिलाएं सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन कर कामयाबी के झंडे बुलंद कर रही हैं।

बागेश्वर निवासी **भावना धपोला** का कहना है कि कोई राज्य एवं समाज तभी विकसित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति सशक्त हो। राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के साथ ही 'मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना', मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। धामी सरकार द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार योजना व नंदा गौरा योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि में भी बढ़ोतरी कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम किया जा रहा है। लोगों के दिलों में मुख्यमंत्री धामी नारी सशक्तिकरण के नए मसीहा के रूप में उभर रहे हैं।

जीआई टैग रिकॉर्ड देवभूमि के नाम

वर्ष 2023 उत्तराखण्ड के इतिहास में कई उपलब्धियों को लेकर आया। इनमें एक जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है। एक दिन में ही 18 जीआई टैग पाकर उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन चुका है। इससे उत्तराखण्ड की चौलाई, झंगोरा, रम्माण के मुखोटे और कुमाऊंनी रंगवाली पिछोड़ा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी

जीआई प्रमाण पत्र देते सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

संजय कुंवर

उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक १८ जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। गत् दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। ये उत्तराखण्ड के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है कि यहां के मौलिक उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलती जा रही है। अब तक उत्तराखण्ड के कुल २७ उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। उत्तराखण्ड के ये सभी उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखने को मिलेंगे और आप इन्हें विभिन्न देशों में खरीद सकते हैं। उम्मीद की जा रही कि भविष्य में ये उत्पाद वैश्विक पहचान बनाने में सफल होंगे। स्थानीय प्रोडक्ट के प्रचार-प्रसार में जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय प्रोडक्ट को देश के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाने में जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जीआई टैग मिलने के बाद न केवल उत्पादों को बाजार मिलेगा अपितु लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

इन १८ को मिला जीआई प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, काला भट्ट, बिच्छूबूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊंनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रम्माण मास्क तथा लिखाई वुड कार्विंग शामिल हैं।

ये है जीआई टैग

वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑर्गनाइजेशन (विप्रो) के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रांतीय और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भारतीय संसद में सन् १९९९ में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 'जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स' लागू किया था, इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। ये टैग किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली या फिर तैयार की जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर-कानूनी प्रयोग को रोकना है।

भारत में ये टैग किसी खास फसल, प्राकृतिक और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला-जुला जी आई टैग दिया जाता है। उदाहरण के लिए बासमती चावल है जिस पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है।

इन नौ उत्पादों को पहले ही मिल चुका है जीआई टैग

उत्तराखण्ड के नौ उत्पादों तेजपत्ता, बासमती चावल, ऐपण आर्ट, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, च्यूरा ऑयल तथा ताम्र उत्पाद को पहले ही जीआई टैग भौगोलिक संकेतांक (जियोग्राफिकल इंडिकेशंस) प्राप्त हो चुका है। तेजपत्ता प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद था। जीआई टैग को हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। इसके अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थाओं को दिए जा सकते हैं, एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद १० सालों तक ये टैग मान्य होते हैं, जिसके बाद इन्हें फिर रिन्यू करवाना पड़ता है। पहला जीआई टैग साल २००४ में दार्जिलिंग चाय को मिला था।

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 03 फरवरी, 2024

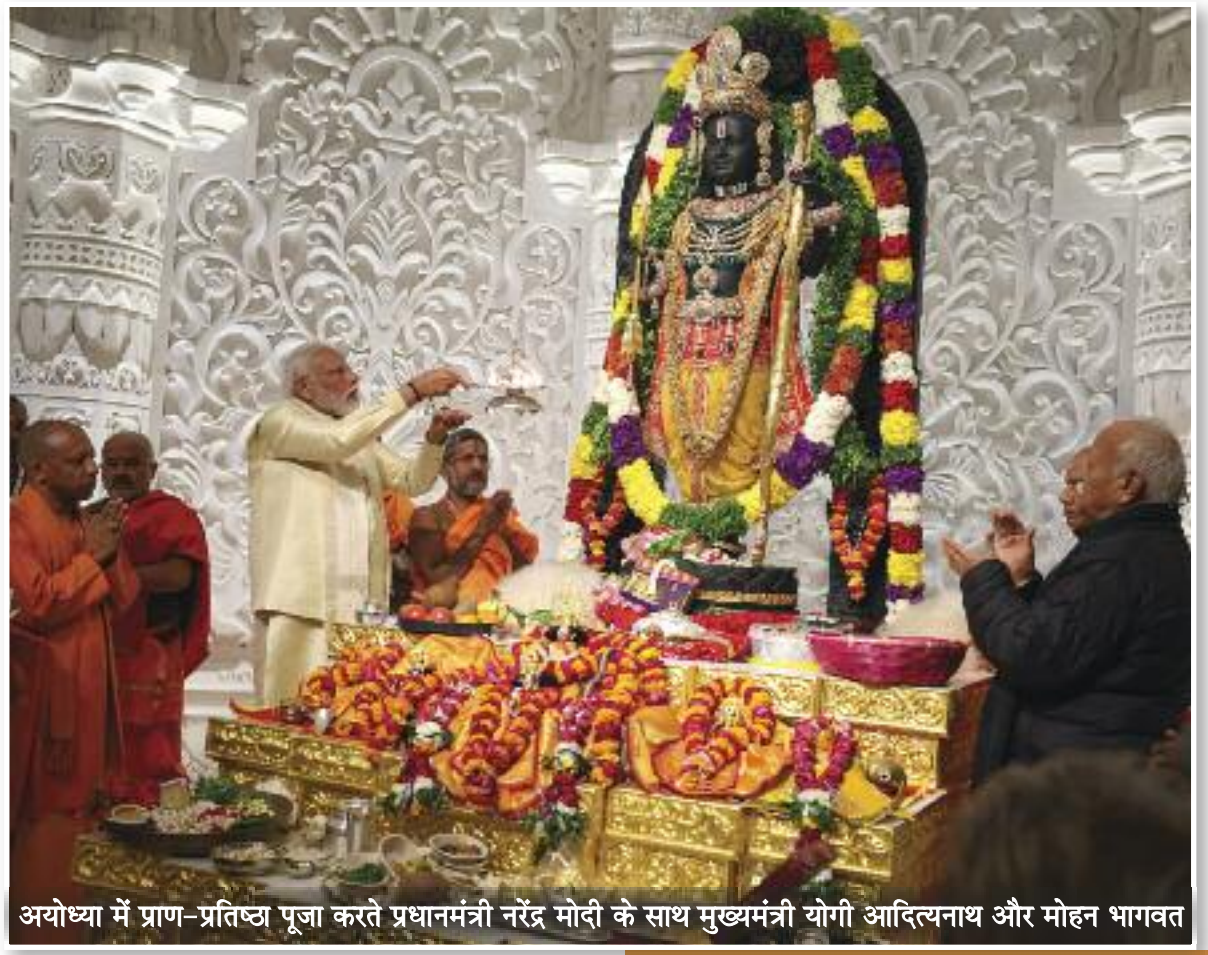

अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा पूजा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत

हिंदू धर्म के शीर्ष धर्मगुरुओं द्वारा आपत्ति उठाए जाने को दरकिनार करते हुए अयोध्या में निर्माणाधीन राममंदिर में रामलला की मूर्ति का सफल प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा पूरे देश में यह संदेश दे पाने में सफल रही कि नरेंद्र मोदी ही असल हिंदू हृदय सम्राट हैं और उनके नेतृत्व में ही भारत अपने गौरवशाली अतीत को वापस ला सकता है। उच्चतम न्यायालय के कई पूर्व न्यायाधीशों, कॉरपोरेट की दुनिया के दिग्गजों और फिल्मी सितारों से लेकर आम हिंदू मतदाता राममंदिर निर्माण को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मान जिस तरह से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है उससे स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी की राह रोक पाना विपक्षी दलों के लिए लगभग असंभव हो चला है

घर-घर राम

◎ जीवन सिंह टनवाल

देश में इन दिनों एक ओर जहां आगामी आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं वहीं सैकड़ों वर्षों से चली लंबी लड़ाई और फिर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले बाद आखिरकार भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में २२ जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित कई उद्योगपति और बड़ी हस्तियां शामिल हुए।

रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा 'हमारे राम आ गए हैं। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्रीराम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। ''प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर अदालत के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। राम मंदिर से जुड़े विवाद की ओर संकेत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत की सामाजिक विवेक को नहीं जान पाए। राम आग नहीं ऊर्जा हैं। राम विवाद नहीं, समाधान हैं। राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, सबके हैं। राम सिर्फ वर्तमान नहीं, अनंतकाल हैं। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों के इंतजार के बाद ये पल आया है अब हम रुकेंगे नहीं।''

पीएम के इस भाषण को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने २०२४ के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषण में राम के आने की बात कहकर एक बड़ा राजनितिक संदेश दिया है। पीएम ये बताना चाह रहे हैं कि राम को बीजेपी और आरएसएस लेकर आए हैं। जो आने वाले चुनाव को देखकर कहा गया है। इस कार्यक्रम से पहले जिस तरह से देशभर में झंडे बांटे गए और भजन-कीर्तन हुआ इससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सिर्फ बीजेपी ही हिंदुओं की एक मात्र रक्षक है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मानना है कि कांग्रेस जिस तरह 'तुष्टिकरण' की नीति चलाती रही है उससे देश में अस्सी फीसदी होते हुए भी हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बने रहते। भाजपा लोगों में हिंदू गर्व भरने में कामयाब रही है और हिंदुओं की एक बड़ी आबादी इस भावना में बहने भी लगी है। राजनीतिक विश्लेषक लेकिन मानते हैं कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। सारे राम भक्त बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। अगर सारे हिंदू राम के नाम पर बीजेपी को वोट देते तो इसे कम से कम ८० फीसदी नहीं तो ६० फीसदी वोट मिलते ही मिलते। राम के भक्त को भारतीय जनता पार्टी का वोटर मानना ठीक नहीं होगा। ये भी नहीं कि भाजपा को इसका कोई लाभ नहीं होगा। जाहिर है फायदा होगा क्योंकि बीजेपी ने ३० साल तक इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तमाम हार-जीत, कानूनी लड़ाई, संसद की राजनीति, के बाद भव्य राम मंदिर बना है। बीजेपी इसका फायदा क्यों न उठाए। इसके अलावा भाजपा के पास मोदी की गारंटी नामक चुनावी हथियार भी है जिसे पार्टी चुनाव में जोर-शोर से उठाएगी।

भाजपा को लग रहा है कि २०२४ के चुनाव में अगर बीजेपी को उत्तर भारत में कोई झटका लगता है तो दक्षिण में कुछ सीटें जीतकर वो इसकी भरपाई कर सकती है। बीजेपी दक्षिण भारत में अपना विस्तार करना चाहती है। मोदी जी का हर कदम राजनीतिक और चुनावी होता है। जिस तरह वो दक्षिण में मंदिर-मंदिर घूमे हैं उससे यही संकेत मिलते हैं। हालांकि उत्तर भारत में बीजेपी की सीटों में कोई कमी आएगी ऐसा हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर भारत या हिंदी बेल्ट की पार्टी होने का जो टैग लगा है उसे खत्म किया जाए। मोदी की गारंटी और मंदिर को वो दक्षिण भारत में भी प्रयोग करना चाहते हैं।

खास बात यह कि तमाम आपत्तियों को दरकिनार कर इस मंदिर के प्रसंग के कारण पूरा देश 'राम' के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिस तरह से आयोजन किया उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आम चुनाव से ठीक पहले मंदिर की राजनीति के जरिए भी भाजपा इंडिया गठबंधन को घेरना चाहती है। वैसे भी कई विपक्षी दलों ने कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। ऐसे में बीजेपी काफी आसानी से उन्हें हिंदू विरोधी बात कर एक विशेष वर्ग को अपने पाले में करना चाहती है। इस माहौल में सवाल उठ रहे हैं कि इस प्रसंग को धार्मिक या आध्यात्मिक कहा जाए या राजनीतिक? क्योंकि आध्यात्म के साथ राजनीति भी इस घटनाक्रम से जुड़ी नजर आ रही है और राजनीति का इससे तालमेल भी किसी से छुपा नहीं है। इसके साथ ही यह भी प्रश्न उठ रहा है कि अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आने वाली रामनवमी (राम जन्मदिवस) के बजाए अभी क्यों किया गया? क्या इस पवित्र धार्मिक कार्य को रामनवमी के दिन नहीं किया जा सकता था? क्या भाजपा इसके जरिए लोकसभा चुनाव २०२४ में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रामनवमी तक देश में आम चुनाव होने हैं। जिसमें कुछ ही महीनों का समय शेष है। ऐसे में आचार संहिता लागू हो जाती और सत्तारूढ़ दल को उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इस आध्यात्मिक कार्य के लिए बाईस जनवरी के दिन का चयन किया गया।

असल में भाजपा सभी विरोधी पार्टियों को अपनी रणनीतिक पिच पर बुला रही है। राहुल गांधी बजरंगबली का मुखौटा पहने नजर आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल सुंदर कांड करा रहे हैं। फिर भी देश में यह पहली बार हुआ है कि वामपंथी और कांग्रेस को एक दक्षिणपंथी व्यक्ति ने ध्वस्त कर दिया है।

कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जग जाहिर है कि भाजपा शुरू से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति करती रही है। यह जनसंघ के जमाने से रहा है। यह उनके डीएनए का हिस्सा रहा है, मगर विपक्ष की कमजोरी का एक कारण यह है कि वह मूल बातों को नजरअंदाज करती हैं। यह कहना कि राम के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है वह गलत है। जिस प्रकार कई दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरोप लगाए कि यह भाजपा का राजनीतिक आयोजन है और इसे २०२४ के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसके लिए कई अहम बातों को नजरअंदाज किया गया। विरोध करने वाले ज्यादातर दल अब अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव २०१९ में भी इसी तरह की बातें हो रही थीं। २०२४ के चुनाव नतीजों के बाद भी इस तरह की बात हो सकती है क्योंकि जमीनी स्तर पर जो सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं उसकी वजह से हजारों मतदाता भाजपा के साथ जुड़े हैं। ये वोटर सिर्फ मंदिर की वजह से नहीं जुड़े हैं। देश का ५० फीसदी वोटर पिछड़ी जाति से आता है। वह भाजपा के साथ क्यों है यह भी समझना होगा।

22 जनवरी 2024 को जय श्री राम की रैली

ईरान का मिसाइल हमला

तनाव की जकड़ में मध्य पूर्व

हवाई हमलों के विरोध में ईरान और इज़राइल दोनों के खिलाफ प्रदर्शन

फोटो : वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू पोर्टल से साभार

दि संडे पोस्ट डेस्क

ईरान और पाकिस्तान के मध्य तनाव तेजी से बढ़ने लगा है। इस तनाव के पीछे जैश-अल-अद्ल नाम का एक आतंकी संगठन है जो खुद को ईरान में रह रहे सुन्नी मुसलमानों का रक्षक बताता है। ईरान ने इसी संगठन के पाकिस्तान स्थित ठिकानों पर मिसाइल हमला गत १६ जनवरी को कर दिया जिसके बाद दोनों देशों के मध्य तनाव गहरा गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और ईरान ९०० किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। यह सीमा ईरान के सिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मध्य है। दोनों ही देश लंबे समय से एक-दूसरे पर आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं।

बलूचिस्तान है विवाद की जड़

ईरान एक शिया बाहुल्य देश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुन्नी बहुमत वाला मुस्लिम राष्ट्र है। दोनों देशों के मध्य कोई सीमा विवाद नहीं है। पाकिस्तान को बतौर राष्ट्र सबसे पहले ईरान ने ही मान्यता दी थी लेकिन बलूचिस्तान के मुद्दे पर दोनों के मध्य तनाव लंबे अर्से से रहता आया है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान का एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग आजादी उपरांत से ही करता आया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने तथा प्राकृतिक संसाधनों की यहां बहुतायत होने के बावजूद भी यह बेहद पिछड़ा और अविकसित हैं। बलूचियों को पाकिस्तान से शिकायत है कि उनके साथ उपनिवेश सरीखा व्यवहार किया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाफ यहां कई अलगाववादी संगठन सक्रिय रहते आए हैं। बलूच जनजाति की एक बड़ी तादात ईरान के सिस्तान प्रांत में भी रहती है। ईरानी बलूचों का आरोप है कि शिया बाहुल्य ईरानी सरकार उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाती है। पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी संगठन ईरानी बलूचियों के समर्थन में कई बार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कि उसके खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठन सिस्तान प्रांत में मौजूद हैं और उन्हें ईरानी सरकार का समर्थन प्राप्त है।

पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के लिए गत 16 जनवरी का दिन बेहद हैरान और परेशान करने वाला रहा। इस दिन ईरान की सेना के रिवोल्यूशनरी कोर गार्ड ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सर्जिकल स्ट्राइक कर वहां मौजूद दो आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। हालांकि इस हमले के जवाब में 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद दो बलूचिस्तानी अलगाववादी संगठनों पर हमला कर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह जवाबी कार्यवाही करने में समर्थ है लेकिन चौतरफा संकटों का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए ईरान के तेवर बड़ी समस्या बन सकते हैं

निशाने पर जैश-अल-अद्ल

ईरान सरकार लंबे अर्से से पाकिस्तान पर 'जैश-अल-अद्ल' नामक आतंकी संगठन को समर्थन देने और बलूचिस्तान में इस संगठन के ठिकाने होने का आरोप लगाती रही है। यह संगठन वर्तमान में बलूचिस्तान-सिस्तान इलाके में सक्रिय सबसे मजबूत आतंकी संगठन है। २००३ में इस संगठन ने ईरान सरकार के कई दफ्तरों में हमले किए थे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजाद की हत्या का प्रयास भी किया था। अक्टूबर, २००९ में इस आतंकी संगठन ने ईरान के पिशिन शहर पर आतंकी हमला बोला था जिसमें ईरानी रिवोल्युशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर मारे गए थे। इस हमले बाद ईरान और पाकिस्तान के संबंध खासे तल्ख हो गए। अक्टूबर, २०२३ में इस संगठन ने १४ ईरानी सैनिकों की हत्या कर दी थी। इससे पहले अप्रैल, २०१७ में भी फिर इसने १० ईरानी सैनिकों को मार डाला था। २०१९ में अमेरिका ने जैश-अल-अद्ल को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया।

पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही

पाकिस्तान के लिए ईरान द्वारा किया गया हमला बेहद आश्चर्यजनक था। १६ जनवरी के दिन ही पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकड़ और ईरानी विदेश मंत्री की दावोस (स्विजरलैंड) में लंबी मुलाकात हुई थी। ऐसे में यकायक ईरान द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र में मिसाल हमला पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बेहद आश्चर्यजनक बताया जा रहा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। १८ जनवरी की सुबह पाकिस्तानी सेना ने एक सैन्य अभियान चला ईरान में शरण लेकर रह रहे आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर दिए। ईरान के सिस्तान प्रांत के एक गांव में कई मिसाइल गिराई गईं जिनमें तीन महिलाओं और चार बच्चों समेत नौ लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 'पाकिस्तान द्वारा ईरान को कई बार इस बाबत सबूत दिए गए कि उनके प्रांत में पाकिस्तान विरोधी आतंकी सक्रिय हैं। ईरान द्वारा कोई कार्यवाही न करने के बाद ही पाकिस्तान को यह हमला करना पड़ा।'

कुल मिलाकर ईरान-पाकिस्तान के मध्य तनाव गहराने का बड़ा असर इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल -हमास युद्ध ने पहले से ही वैश्विक स्तर पर चिंताओं को जन्म दे दिया है, ऐसे में ईरान-पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थिति आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने का कारण बन सकती है।

ट्रम्प के आने की आहट से चौतरफा खलबली

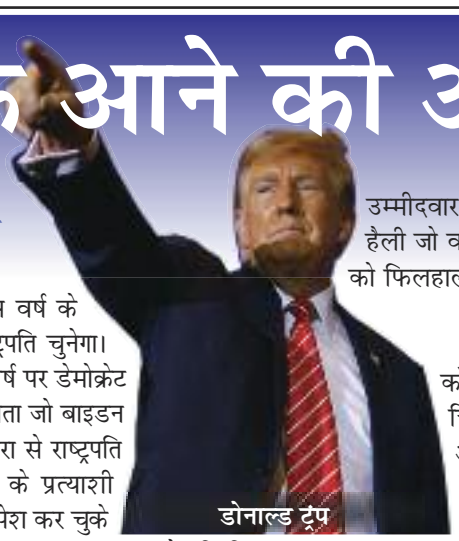

डोनाल्ड ट्रंप

दि संडे पोस्ट संवाददाता

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस वर्ष के अंत में अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा। वर्तमान में अमेरिकी सत्ता के शीर्ष पर डेमोक्रेट पार्टी का कब्जा है और उसके नेता जो बाइडन राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा से राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी बतौर अपनी दावेदारी न केवल पेश कर चुके हैं, बल्कि अमेरिकी चुनाव व्यवस्था अनुसार बतौर रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी एक राज्य आयोवा में जीत भी दर्ज करा चुके हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों की हरेक राज्य में अपने-अपने दल के प्रत्याशियों संग प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होता है। सबसे अधिक राज्यों में जीत दर्ज कराने वाला प्रत्याशी ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ६ नेताओं ने मुख्य तौर पर राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने का दावा किया था। इनमें डोनाल्ड ट्रम्प, रोनाल्ड डायोन, कोन डीसेन्टिल, निक्की हैली, विवेक रामास्वामी प्रमुख दावेदार थे। आयोवा में ट्रम्प की जीत के बाद विवेक रामास्वामी ने ट्रम्प का समर्थन करते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पहले दो अन्य प्रत्याशी भी मैदान से बाहर हो गए थे। फ्लोरिडा प्रांत के गवर्नर डोनाल्ड डायोन शुरुआती चरण में ट्रम्प के सबसे मजबूत विरोधी बन उभरे थे लेकिन विवेक रामावामी द्वारा नाम वापस लेने के चंद दिनों बाद रोनाल्ड ने भी अपना नाम वापस लेते हुए ट्रम्प को सर्थन दे डाला है। अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दो उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय मूल की नम्रता निक्की रंधावा हैली जो वर्तमान में दक्षिण कैरोलाइना प्रांत की गवर्नर हैं, ट्रम्प को फिलहाल चुनौती देती नजर आ रही हैं।

डेमोक्रेट पार्टी में खलबली

बतौर रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को आयोवा प्रांत में मिली जीत ने डेमोक्रेट पार्टी की चिंता में भारी इजाफा करने का काम किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रम्प की आयोवा प्रांत में जीत के बाद दिए एक बयान में कहा है कि वे बेहद डरी हुई हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। कमला हैरिस ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि 'मुझे बहुत डर लग रहा, यही वजह है मैं देशभर का दौरा कर रही हूं.. हम सभी को डरना चाहिए। हालांकि जब हम डरते हैं तो भागते नहीं हैं, बल्कि उसके खिलाफ लड़ते हैं।'

दरअसल, रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकियों को यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि ट्रम्प का दोबारा राष्ट्रपति बनना उनके देश के लिए खासा घातक साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लगातार ट्रम्प की संभावित वापसी को लेकर जनता को चेता रहे हैं। उनका कहना है कि दो बार महाभियोग का सामना कर चुके ट्रम्प पर ९१ आपराधिक मामले भी दर्ज है इसलिए उनका दोबारा राष्ट्रपति बनना अमेरिकी लोकतंत्र के लिए भारी खतरा बन सकता है।

ट्रम्प की उम्मीदवारी पर कानूनी पेंच

बतौर रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रम्प अपनी पार्टी के अन्य दावेदारों से आगे निकलते स्पष्ट नजर आ रहे हैं लेकिन दोबारा से राष्ट्रपति बनने की उनकी राह में अभी लंबी कानूनी लड़ाई बाकी है। अमेरिका के दो राज्यों ने उनकी दावेदारी पर बड़ा प्रश्न चिह्न लगाते हुए राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने से रोक दिया है। ट्रम्प को पहला झटका गत् दिसंबर में कोलोराडो राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ६ जनवरी २०२१ को अमेरिकी संसद यूएस कैपिटल में ट्रम्प समर्थकों द्वारा उनके चुनाव हारने के बाद किए गए हमले को लेकर ट्रम्प की भूमिका पर प्रश्न उठाते हुए कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के प्राथमिक मतदान में शामिल होने के लिए अयोग्य करार दे दिया है। इसके बाद एक अन्य प्रांत मेन के चुनाव आयोग ने भी संसद भीतर हमले के लिए ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको प्राथमिक चुनाव लड़ने से रोक दिया है। अब इन मामलों की सुनवाई अमेरिकी संघ की सुप्रीम कोर्ट में अगले माह होने जा रही है। ट्रम्प के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पात्रता का प्रश्न राज्यों की अदालतें तय नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोका नहीं गया तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा कि न्याय पालिका ने एक प्रमुख पार्टी के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार मतदाताओं से छीना होगा।

बहरहाल, ट्रम्प के चलते इस बार का अमेरिकी चुनाव खासा रोचक होता जा रहा है। अपनी विवादित कार्यशैली और उत्तेजक बयानों के चलते हमेशा चर्चाओं में रहने वाले डोनाल्ड ट्रम्प की राह में हालांकि अभी खासी अड़चनें बाकी हैं लेकिन तमाम विवादों और अड़चनों के बावजूद वे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार बन उभर चुके हैं।

उत्तराखण्ड शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एक ही लक्ष्य-एक ही सपना
सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखण्ड अपना

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

आगे बढ़ता उत्तराखण्ड

• मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पांच जनपदों क्रमशः चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी एवं उ0सि0नगर के 09 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सामुदायिक / समग्र विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्य संवर्धन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें ससमय उपलब्ध कराना है ताकि सीमान्त क्षेत्रों में पलायन को भी रोका जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 2000.00 लाख की धनराशि सीमान्त जनपदों हेतु स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष रू0 शत प्रतिशत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है।

• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास निवारण आयोग द्वारा चिन्हित गांवों में आवासित परिवारों / बेरोजगार युवाओं / रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रूप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम पलायन रोकना तथा रिर्वस पलायन को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 2500 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है।

• वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 285, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितम्बर, 2023 तक 95 योजना प्रारम्भ (वर्ष 2002) से आतिथि तक 7257 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

• दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 222, वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में सितम्बर 2023 तक 61, योजना प्रारम्भ से आतिथि तक 671 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

• ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे के अन्तर्गत 06 जनपदों में 16 ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर के अन्तर्गत 99 गांव को अब तक अधिसूचित किया गया है तथा 304 व्यक्तियों का चयन योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

• पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित Best Tourism Village Competition के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के सरमोली गांव को भारत सरकार की गोल्ड केटेगरी में Best Tourism Village का अवार्ड प्रदान किया गया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in UttarakhandDIPR DIPR_UK UttarakhandDIPR

RO2024012521632

यही समय है, सही समय है,

उत्तराखण्ड में निवेश का

DESTINATION UTTARAKHAND
GLOBAL INVESTORS SUMMIT 2023
Peace To Prosperity

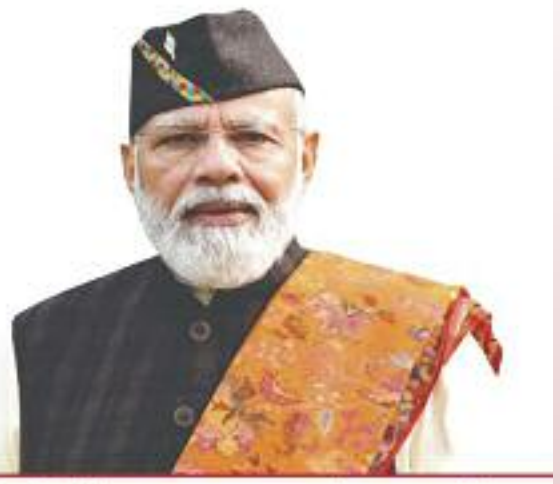

"माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड की आर्थिकी और पर्यटन विकास में वृद्धि हुई है। हमारा राज्य व्यापार के लिए सदैव खुला है, जो निवेशकों को व्यापक अवसर प्रदान करता है। सुव्यवस्थित उद्योग की मंजूरी से लेकर निवेशकों को प्रोत्साहित करने तक हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्यमों के लिए एक सम्पन्न पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। आइये मिलकर उत्तराखण्ड के भविष्य को नया आकार प्रदान करें।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

"21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, उत्तराखण्ड का दशक है। उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है, जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है। वह दिन दूर नहीं, जब दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी ढाई घंटे की रह जाएगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह सब कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है।"

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

- उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न
- निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर
- 44 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ
- सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री धामी और राज्य प्रशासन को मिली बधाई
- 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'वेड इन इंडिया' आंदोलन शुरु करने का प्रस्ताव
- ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज लॉंच
- 30 से अधिक नीतियां लागू करके नीति-संचालित राज्य का सम्मान
- उत्तराखण्ड में भव्य कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की योजना

दुनियाभर के निवेशकों की पहली पसंद बनता उत्तराखण्ड आज निवेश की नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रदेश में निवेश की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से 8-9 दिसंबर को 'उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह राज्य को नए निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कारगर कदम साबित हुआ। इस सम्मेलन में दुनियाभर के हजारों निवेशकों और प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई अन्य केंद्रीय एवं राज्य मंत्री, दुनियाभर के बड़े-बड़े उद्योगपति, व्यवसाय जगत से जुड़ी सुप्रसिद्ध हस्तियां, विभिन्न देशों के मेयर, 16 देशों के राजदूत और 5 हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 'पीस टू प्रोस्पेरिटी (शांति से समृद्धि)' थीम पर आधारित इस समिट का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड को निवेश का गंतव्य प्रदेश बनाना है।

'उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' की ऐतिहासिक सफलता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरगामी विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक परिश्रम का परिणाम है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 'वाइब्रेंट गुजरात' नाम से इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुरू किया था। उसी से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 'डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड' की थीम पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया।

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन राज्य को नए निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कारगर कदम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों की बदौलत इस कार्यक्रम को उम्मीद से परे सफल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखण्ड की अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डालते हुए निवेशकों से इसका अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है। राज्य सरकार जहां स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, वहीं भारत सरकार उत्तराखण्ड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है।

8 -9 दिसंबर को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। समिट के उद्घाटन के साथ-साथ उन्होंने 'सशक्त उत्तराखण्ड पुस्तक' और 'ब्रांड-हाउस ऑफ हिमालयाज' को भी लॉन्च किया। वहीं, 9 दिसंबर को उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के समापन समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति ने दुनियाभर के निवेशकों का हौसला बढ़ाया। समिट के उद्घाटन सत्र में कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए। इसमें भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही उत्तराखण्ड सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक आदि उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में 9 प्रमुख वक्ता के रूप में देश के प्रमुख उद्योगपति शामिल रहे। 15 राजदूत, हेड ऑफ मिशन-कोस्ट, स्लोवेनिया, नेपाल, बल्गेरिया, चीली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साऊदी अरब आदि शामिल रहे। वहीं, 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के समापन सत्र में प्रतिभाग किया।

'डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड' का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार के साथ इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के समन्वय द्वारा राज्य का समग्र विकास करना है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अभी तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौते हो चुके हैं। इनमें से अब तक 44 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इससे प्रदेश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य गतिमान है। सरकार निवेश के जरिए राज्य में रोजगार सृजन एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत अभी तक तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड में निवेशकों द्वारा जो रुचि दिखाई गई है, इससे राज्य की प्रगति में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रदेश में हेल्थ, वेलनेस, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, फार्मा और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए, इन क्षेत्रों में विशेष फोकस किया जा रहा है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों को सरल बनाया गया है। निवेशकों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां तैयार की गई हैं।

समिट में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं बातचीत हुई। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य सरकार ने जिन निवेशकों से निवेश के लिए एमओयू साइन किए हैं, उनमें प्रमुखतः टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, आयुष वेलनेस, नेन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट-हेल्थ, पेपर स्टोरेज, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल हैं। उत्तराखण्ड में निहित शिक्षा सामर्थ्य को संवारने के लिए इन्वेस्टर्स समिट के तहत विद्यालयी, तकनीकी और उच्च शिक्षा का द्वितीय सत्र निवेशकों के साथ आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के जरिए राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शोधार्थियों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है।

'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर शुरू करें 'वेड इन इंडिया': पीएम मोदी

धार्मिक, आध्यात्मिक, हसीन वादियों, हरे-भरे और बर्फीले पर्वतों का गढ़ है देवभूमि उत्तराखण्ड। जो बेहतर कनेक्टिविटी, शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर और सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है। धामी सरकार राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन के साथ-साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की परंपरा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है और इससे संबंधित सुविधाएं लगातार विकसित की जा रही हैं। लोग उत्तराखण्ड के पवित्र धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थलों पर डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद, यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड 'डेस्टिनेशन वेडिंग' के गंतव्य के रूप में अपनी जगह बना सकता है।

देवभूमि उत्तराखण्ड वह पवित्र स्थल है, जो अपने विवाह समारोह के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगीनारायण गांव में स्थित श्री त्रियुगीनारायण मंदिर उनमें से एक है। ऐसी मान्यता है कि यही वह स्थान है, जहां भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ सात फेरे लिए थे। यही कारण है कि यहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जोड़ियां शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं। यह स्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में नई पहचान बना रहा है।

इसी प्रकार, धनौल्टी हरिद्वार के शांतिकुंज में हर साल बड़ी संख्या में जोड़े विधि-विधान के साथ जन्म-जन्मांतर की डोर में बंधते हैं। तीर्थनगरी ऋषिकेश की बात की जाए तो मौजूदा समय में यह स्थल देश-विदेश के युवाओं के लिए प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। मसूरी, नैनीताल और रामनगर सभी आलीशान सुख-सुविधाओं से संपन्न स्थलों में एक हैं, जिनके वेडिंग डेस्टिनेशन का चलन देश-विदेश तक बढ़ रहा है। प्रकृति की गोद में विवाह करने के लिए उत्तराखण्ड में ओली जैसे हिल स्टेशन यानी जिनी रिवेट्जरलैंड भी है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन और तीर्थाटन की विकसित सुविधाओं की वजह से यहां वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के 'वेड इन इंडिया' के नारे के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि धामी सरकार इस मुहिम की दिशा में तेज गति से काम करेगी। 'वेड इन इंडिया' आंदोलन आने वाले समय में उत्तराखण्ड को वेडिंग के लिए सबसे पसंदीदार डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाएगा। इससे स्थानीय कारोबार में वृद्धि के साथ आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे।

उत्तराखण्ड सरकार की प्रमुख नीतियां

प्रमुख नीतियाँ

- सेवा क्षेत्र नीति 2023
- सौर ऊर्जा नीति 2023
- एमएसएमई नीति 2023
- स्टार्ट-अप नीति 2023
- कस्टमाइज्ड पैकेज
- लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023
- फिल्म नीति 2015 (2019 में संशोधित)
- निजी औद्योगिक पार्क नीति 2023
- वृहद् औद्योगिक नीति 2015
- निर्यात नीति 2021
- पर्यटन नीति 2023-30
- ड्रोन नीति 2023
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2019
- आयुष एवं वेलनेस नीति
- जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018-23
- खाद्य प्रसंस्करण नीति
- पंप भंडारण परियोजना नीति 2023

रोड शो के जरिए उम्मीद से परे निवेश

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की अभूतपूर्व सफलता की वजह से आज उत्तराखण्ड दुनियाभर के निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशशिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महीनों पहले से तैयारियां की गईं। समिट के प्रचार-प्रसार के लिए देश-विदेश में कई 'रोड शो' किए गए थे, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय और 7 घरेलू 'रोड शो' शामिल हैं।

3 अंतर्राष्ट्रीय रोड शो जहां लंदन, बर्मिंघम और दुबई में आयोजित किए गए, वहीं 7 घरेलू रोड शो दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में आयोजित हुए। दरअसल, ऐतिहासिक उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के भव्य आयोजन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निरंतर कड़े प्रयास किए गए।

यह उसी कठिन परिश्रम का परिणाम था कि समिट के आयोजन से पहले ही 14 सितंबर-4 अक्टूबर, 2023 को धामी सरकार द्वारा दिल्ली में 26,575 करोड़ रुपए, 26-28 सितंबर को लंदन में 12,500 करोड़ रुपए, 17-18 अक्टूबर को दुबई में 15,475 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ। वहीं, रोड शो के दौरान 26 अक्टूबर को चेन्नई में 10,180 करोड़ रुपए, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में 4,600 करोड़ रुपए, 1 नवंबर को अहमदाबाद में 24,000 करोड़ रुपए और 6 नवंबर को मुंबई में 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए।

यही समय है, सही समय है,

उत्तराखण्ड में निवेश का

DESTINATION UTTARAKHAND
GLOBAL INVESTORS SUMMIT 2023
Peace To Prosperity

"भारतीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड की आर्थिकी और पर्यटन विकास में वृद्धि हुई है। हमारा राज्य व्यापार के लिए सदैव खुला है, जो निवेशकों को व्यापक अवसर प्रदान करता है । सुव्यवस्थित उद्योग की मंजूरी से लेकर निवेशकों को प्रोत्साहित करने तक हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्यमों के लिए एक सम्पन्न पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। आइये मिलकर उत्तराखण्ड के भविष्य को नया आकार प्रदान करें।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

"21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, उत्तराखण्ड का दशक है। उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है, जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है। वह दिन दूर नहीं, जब दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी ढाई घंटे की रह जाएगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह सब कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है।"

नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री

बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में निवेश

कल्याण चक्रवर्ती, सीईओ, एमार ग्रुप

05 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा एमार ग्रुप

एमार इंडिया के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में हमें गौरव मिल रहा है जिससे 10 साल से जो चर्चा आया है, विश्व के कारोबार में यह पहले कभी नहीं था उन्होंने भारत-यूएई संबंधों में नई गतिशीलता की ओर भी इशारा किया। चक्रवर्ती ने कहा कि एमार ग्रुप का हेड ऑफिस संयुक्त अरब अमीरात में है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूएई के साथ हमारे रिश्तों ने नए परवान पर पहुंच गए हैं। एमार तुर्की, अमेरिका के विनिर्माताओं के साथ में काम कर रहा है। इस भारत में भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे भारत का सिर ऊंचा रहे, प्रधानमंत्री का सिर ऊंचा रहे। कुछ नया करके दिखाएं। उन्होंने सीईआरसी और डिजिटल इंडिया की तारीफ की। उन्होंने फिनटेक क्रांति में यूपी कॉर्पोरेशन सुधारों का उल्लेख किया, जो औद्योगिक जगत के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखण्ड में अपने ग्रुप की इच्छा है कि स्थायी रूप से कुछ किया जाए। अगले पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश एमार ग्रुप करेगा। इसमें टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, टीओडी, डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरलिंग डेवलपमेंट व मिक्स यूज होगा। अर्बन इमर्जे लिंकअप में इन्वेस्ट किया जाएगा।

उत्तराखण्ड के गुलाब से बनेगा रसना हिमालयन शरबत

गिरीश संघाटा, प्रबंध निदेशक, रसना

उत्तराखण्ड के एमडी गिरीश संघाटा ने कहा है कि वो उत्तराखण्ड के गुलाब से प्रीतिस्पर्श बनाते हुए, इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान पत्रकारों से बातचीत में संघाटा ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अब तक पारंपरिक और अपारंपरिक खेती के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन अब उत्तराखण्ड को लेकर उत्तर भारत का नजरिया बदल रहा है। इसी क्रम में रसना ने उत्तराखण्ड में उगने वाले गुलाब का परीक्षण किया है, जो पारंपरिक औषधीय गुणों से भरपूर है। अब कंपनी इस गुलाब से हिमालयन गुलाब जल, हिमालयन गुलाब ओयल, हिमालयन अर्क, हिमालयन गुलकंद और हिमालयन चायजाम तैयार कर बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। संघाटा ने कहा कि रसना ने पहाड़ों में उगने वाले फल के होने वाले आम के साथ भी किया था। सफल रहा, अब उत्तराखण्ड में इसे लेकर काम करना चाहता है। उत्तराखण्ड दिल्ली के करीब है, कनेक्टिविटी सुधर रही है। उत्तराखण्ड में स्थानीय समस्या नेपाल बेटियों वाली फसलों के सेक्टर में है, अब प्रदेश सरकार राज्य की इस संभावना को समझने लगा है। फूलों की खेती में पता चला है एलएक गुलाब: कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिले में खिलने फूलों की खेती, एलएक नाम के गुलाब के फूलों की खेती के लिए जाना जाता है। यह गुलाब खुशबू सुगंध प्रदान करता है। अगस्त में इसे लॉन्च किया जाएगा।

मल्टी-स्किल हब बनेगा उत्तराखण्ड

आर. विनेश, अध्यक्ष, टीवीएम

10 हजार करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी

वीवीडल उद्योगों वन कॉन्फ्लुएंस के अध्यक्ष आर. विनेश ने कहा कि कंपनी उत्तराखण्ड में एक लाख से अधिक लोगों को पलायन और महापलायन रोकने के लिए 10 स्किल कॉरिडोर केंद्र स्थापित करेगी। उत्तराखण्ड आतिथ्य, स्वास्थ्य देखभाल और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले 10,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की क्षमता वाला स्कोलिंग मल्टी स्किल टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य होगा देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में आर. विनेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने उत्तराखण्ड की विकास यात्रा में कनेक्टिविटी के योगदान, टूरिज्म और ओटी पर्यटकों की विनिर्माण इकाइयों, लॉजिस्टिक्स और ओटी क्षेत्र में संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र और भंडारण क्षमता में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपनी योजनाओं का विस्तार किया, जिससे सभी पारिवारिक कंपनियों में 2,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुईं।

- प्रदेश में हरित ऊर्जा क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के तहत ₹103,459 के 157 एमओयू हस्ताक्षरित
- राज्य में उद्योग को नई ऊंचाई देने के लिए उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा ₹78,448 के 658 एमओयू हस्ताक्षरित
- प्रदेश में पर्यटन विस्तार को नई रफ्तार देने के लिए पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ₹47,646 के 437 एमओयू हस्ताक्षरित
- आवास निर्माण के साथ समृद्धि की गति बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ₹41,947 के 62 एमओयू हस्ताक्षरित
- उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ₹25,785 के 39 एमओयू हस्ताक्षरित
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विकास को नया आयाम देने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ₹19,260 के 175 एमओयू हस्ताक्षरित
- बेहतर सेहत देने के साथ रोजगार के नए सुअवसर पैदा करने के लिए आयुष एवं कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ₹17,058 के 77 एमओयू हस्ताक्षरित
- शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ₹6675 के 28 एमओयू हस्ताक्षरित

30 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जल्द होगा पूरा

02 दिवसीय समिट के पहले दिन किया संबोधित

संजीव पुरी, प्रबंध निदेशक, आईटीसी

आईटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने देश में पिछले दिनों संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वैश्विक दूरदर्शिता और ग्लोबल साउथ लीडरशिप की सराहना की। वह अनुसंधान संस्थान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन शुक्रवार को आईटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में की गई कई नीतिगत पहल से भारत पर बहुआयामी चुनौतियों पर सामना करने वाली स्थिति से हल दिया है। इस अवधि के दौरान देश की अर्थव्यवस्था ने कई दौरों से गुजरना आए है। इसकी मजबूती को जीडीपी के आंकड़े सुदृढ़ करते रहे हैं। पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने पहली स्थिति पैदा कर दी है कि विश्व स्तर पर यह दशक भारत कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सदी भारत की है। उनके नेतृत्व में विकास देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है, उसमें पीएम का 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भी जल्द पूरा होने वाला।

"यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के साथ नए उत्तराखण्ड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। उत्तराखण्ड ने प्राकृतिक सौन्दर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग जगत से जोड़ने का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 से 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावना थी। लेकिन, निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू संपन्न हुए, जो अपेक्षा से बढ़कर हैं। मैं इसके लिए राज्य प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। अब उत्तराखण्ड एक मजबूत राज्य बनेगा। पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ने अब तक अपनी सबसे अधिक प्रगति की है। उत्तराखण्ड ने 6 वर्षों में 30 से अधिक नीतियां लागू करके नीति-संचालित राज्य का सम्मान अर्जित किया है। यहां आपको अच्छे डेस्टिनेशन के साथ-साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने यहां सांस्कृतिक विरासत व विकास के समानांतर कीर्तिमान बनाए हैं। उत्तराखण्ड की उत्कृष्ट कानून व्यवस्था व सुरक्षा ने निवेशकों को अनुकूल वातावरण दिया है। यह समिट देवभूमि के विकास को नई गति देगा।

अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

यही समय है, सही समय है,

उत्तराखण्ड में निवेश का

DESTINATION UTTARAKHAND
GLOBAL INVESTORS SUMMIT 2023
Peace To Prosperity

"माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड की आर्थिकी और पर्यटन विकास में वृद्धि हुई है। हमारा राज्य व्यापार के लिए सदैव खुला है, जो निवेशकों को व्यापक अवसर प्रदान करता है । सुव्यवस्थित उद्योग की मंजूरी से लेकर निवेशकों को प्रोत्साहित करने तक हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्यमों के लिए एक सम्पन्न पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। आइये मिलकर उत्तराखण्ड के भविष्य को नया आकार प्रदान करें।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

"21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, उत्तराखण्ड का दशक है। उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है, जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है। वह दिन दूर नहीं, जब दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी ढाई घंटे की रह जाएगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह सब कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

- उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न
- निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर
- 44 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ
- सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री धामी और राज्य प्रशासन को मिली बधाई
- 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'वेड इन इंडिया' आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव
- ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज लॉंच
- 30 से अधिक नीतियां लागू करके नीति-संचालित राज्य का सम्मान
- उत्तराखण्ड में भव्य कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की योजना

उत्तराखण्ड में निवेश के कई कारण

उत्तराखण्ड में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न सेक्टरों में 'निवेश मित्रों' की नियुक्ति की गई है। ये सभी मित्र 5 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो उत्तराखण्ड में परिवहन मार्गों का तेजी से विस्तार हुआ है। नए एयरपोर्ट के विकास, नई रेलवे लाइन के विस्तार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हेलीपोर्ट और टोपवे के निर्माण द्वारा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखण्ड अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।

वह दिन दूर नहीं, जब दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी मात्र ढाई घंटे की रह जाएगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। प्रदेश में हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार और रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पर्यटकों को प्रकृति के साथ-साथ भारत की विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने की योजना है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने में समेटे उत्तराखण्ड एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। यहां निवेशक योग, आयुर्वेद, तीर्थ और साहसिक खेल आदि के क्षेत्रों में नए अवसर तलाश सकते हैं।

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की मुख्य विशेषताएं

12 से अधिक फोकस सेक्टर | 4 सहभागी देश | 200 से अधिक निवेश अनुकूल परियोजनाएं | 13 जिला स्तरीय इवेंट | 75,000 करोड़ से अधिक देशी निवेश अनुकूल परियोजना लागत | 16 सत्र | 6000 से अधिक एकड़ उपलब्ध लैंडबैंक |

फोकस सेक्टर

- ऑटोमोबाइल्स
- सूचना प्रोद्योगिकी
- हर्बल एवं एरोमेटिक्स
- कृषि एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्र
- जैव प्रोद्योगिकी
- औषधि
- आयुष एवं वेलनेस
- खाद्य प्रसंस्करण
- फिल्म शूटिंग
- हॉर्टिकल्चर एवं फ्लोरीकल्चर
- अक्षय ऊर्जा
- शिक्षा
- पर्यटन
- इलेक्ट्रॉनिक्स
- नेचुरल फाइबर

निवेश जगत में अलग पहचान बनाता उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'युवा नेतृत्व में युवा प्रदेश' जिस गति से आज आगे बढ़ रहा है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच को जाता है। उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए युवा मुख्यमंत्री पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। बाहरी प्रदेशों में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में लगातार सार्थक कदम उठा रहे हैं। सभी को बेहतर औद्योगिक माहौल देने के लिए राज्य की धामी सरकार लगातार प्रयासरत है।

पीएम मोदी द्वारा 'हाउस ऑफ हिमालयाज' का शुभारंभ

31 मिनट समिट को संबोधित किया पीएम ने

उत्तराखण्ड के उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई है। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'हाउस ऑफ हिमालयाज' का शुभारंभ किया गया। इससे अब महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान और वृहद स्तर पर बाजार उपलब्ध होगा। राज्य सरकार के इस अद्भुत प्रयास से अब उत्तराखण्ड के 65,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 5.25 लाख महिलाओं के सामने से अब उनके द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग का संकट दूर होगा। राज्य सरकार ने काफी मेहनत के बाद इन उत्पादों के लिए 'अंबेला ब्रांड' के रूप में 'हाउस ऑफ हिमालयाज' तैयार किया है। इस पहल के प्रथम चरण में भौगोलिक संकेतक प्राप्त राज्य के उत्पादों को प्राथमिकता दी गई है। शीघ्र ही प्रदेश के महिला समूहों के अन्य उत्पादों को इसमें शामिल किया जाएगा।

'हाउस ऑफ हिमालयाज' से महिलाएं सशक्त

महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए आने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 'हाउस ऑफ हिमालयाज' की शुरुआत की गई है। पहले समूह की महिलाएं अपने सभी उत्पादों को अलग-अलग नाम से बिक्री कर रही थीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछली बार अपनी माणा यात्रा के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को सुझाव दिया था कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक 'ब्रांड' होना चाहिए। धामी सरकार ने प्रधानमंत्री के इस विचार पर अमल करते हुए समूहों के उत्पादों के लिए 'अंबेला ब्रांड' बनाने का निश्चय किया। कई उच्च स्तरीय गहन मंथन के बाद इन उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' नाम को अंतिम स्वरूप दिया गया।

उत्तराखण्ड के उत्पादों को मिली नई पहचान

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्य करोड़ों की परियोजनाओं के साथ 'हाउस ऑफ हिमालयाज' नामक 'अंबेला ब्रांड' का शुभारंभ किया। जिसके तहत, अब समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से बाजार में आएंगे। इन उत्पादों की क्वालिटी एवं पैकिंग आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों तक ले जाने का एक अभिनव प्रयास है। देवभूमि उत्तराखण्ड के उत्पाद शहद और सेहत जैसे कई प्राकृतिक गुणों से भरपूर हैं। मौजूदा समय में हिमालय की गोद से निकलने वाले ये उत्पाद हिनाडी, हिलांस और चाम्प-श्री जैसे नामों से बाजार में लाये जाते हैं। लेकिन, अब ये बेमिसाल उत्पाद हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से जाने-पहचाने जाएंगे। यानी उत्तराखण्ड के महिला समूहों द्वारा तैयार अलग-अलग उत्पाद अब 'हाउस ऑफ हिमालयाज' के नाम से दुनियाभर में अपना कमाल दिखाएंगे। हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखण्ड के उत्पादों को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल बनने में मदद करेगा।

यही समय है, सही समय है, उत्तराखण्ड में निवेश का

"माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड की आर्थिकी और पर्यटन विकास में वृद्धि हुई है। हमारा राज्य व्यापार के लिए सदैव खुला है, जो निवेशकों को व्यापक अवसर प्रदान करता है। सुव्यवस्थित उद्योग की मंजूरी से लेकर निवेशकों को प्रोत्साहित करने तक हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्यमों के लिए एक सम्पन्न पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। आइये मिलकर उत्तराखण्ड के भविष्य को नया आकार प्रदान करें!

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

"21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, उत्तराखण्ड का दशक है। उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है, जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है। वह दिन दूर नहीं, जब दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी ढाई घंटे की रह जाएगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह सब कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है।"

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

लखपति दीदी योजना में सहायक होगा 'हाउस ऑफ हिमालयाज'

महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपए करने के उद्देश्य से प्रदेश में लखपति दीदी योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत राज्य में अब तक 40,277 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखण्ड की प्रगति पर केंद्रित प्रदर्शनी में महिला समूहों के स्टाल पर जाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने पौड़ी जिले के जय अंबे महिला स्वयं सहायता समूह और अलकनंदा महिला स्वयं सहायता समूह के मिलेट बेकरी स्टॉल में पहुंचकर इस बारे में जानकारी ली। जय अंबे समूह की गीता रावत व अलकनंदा समूह की उमा देवी ने प्रधानमंत्री को बताया कि पहले उनके समूह अन्य उत्पाद तैयार करते थे। बाद में सरकार ने श्री अन्न को प्रोत्साहित किया तो उनके द्वारा मिलेट बेकरी पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जब प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं से पूछा कि क्या आप लखपति दीदी बन गई हो? तो इस पर गीता रावत और उमा देवी ने बताया कि उनके समूह हर माह मिलेट बेकरी से दो-ढाई लाख रुपए कमा लेते हैं। यानी समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रतिमाह 12-15 हजार रुपए की आय हो रही है। समूह द्वारा स्थानीय अनाजों पर आधारित बेकरी का संचालन अक्टूबर, 2019 से किया जा रहा है, जिसमें मंडुवा, झंगोरा, चौलाई और अन्य अनाजों से विभिन्न प्रकार के बेकरी उत्पाद बनाकर बेचे जा रहे हैं।

हाउस ऑफ हिमालयाज का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा को और मजबूत करता है। उत्तराखण्ड सहित भारत के हर जिले और ब्लॉक के उत्पादों में वैश्विक बनने की क्षमता है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यह एक अद्भुत मंच हो सकता है। हाउस ऑफ हिमालय के लॉन्च के साथ इस पहल को गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश-प्रदेश की महिलाओं को लखपति बनाने का जो मिशन सरकार ने चलाया है, उसे साकार करने में हाउस ऑफ हिमालयाज बड़ी भूमिका निभाएगा। उत्तराखण्ड अनेक संभावनाओं से भरा है और यहां के उत्पाद अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांडिंग के जरिए देश-विदेश में अलग पहचान बनाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है।

हाउस ऑफ हिमालयाज की प्रगति

इस साल की शुरुआत में धामी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी उत्पादों की क्वालिटी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने ही 'हाउस ऑफ हिमालयाज' नाम पर मुहर लगाई है। नाम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड की शुरुआत की जा चुकी है।

प्रदेश स्तर पर जोरशोर से तैयारियां

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन से पहले धामी सरकार द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय और 7 घरेलू 'रोड शो' आयोजित किए गए थे।

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के सफल आयोजन से पहले देश-विदेश के साथ-साथ प्रदेश स्तर पर जोरशोर से तैयारियां की गई थीं। इसी क्रम में देहरादून-हरिद्वार जनपद का हरिद्वार में और नैनीताल-ऊधमसिंह नगर का रुद्रपुर में रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उत्तराखण्ड के सभी छोटे-बड़े उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी 9 जनपदों में 17-30 नवंबर तक 'डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर्स समिट' आयोजित किए गए। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्रदेश की राजधानी देहरादून में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं। इस आयोजन के जरिए दुनियाभर की तमाम बड़ी कंपनियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों को उत्तराखण्ड में निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माहौल के साथ अनुकूल उद्योग नीतियां देखने और समझने का अवसर मिला।

44 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर

इस साल उत्तराखण्ड सरकार ने शत-प्रतिशत ग्राउंडिंग का लक्ष्य रखा था। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के उद्घाटन सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्राउंड वेकिंग सेरेमनी के जरिए 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं में मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से संबंधित 16 परियोजनाएं शामिल हैं। इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत प्रदेश की आर्थिक गति के साथ रोजगार के नए अवसर खोलेगी। उत्तराखण्ड के लिए यह पहला ऐसा अवसर था, जब इतने बड़े स्तर पर निवेश को धरातल पर उतारा गया। इससे लाखों रोजगार सृजन होने की संभावना है।

प्रेरणा से मिली ऐतिहासिक सफलता

देवभूमि उत्तराखण्ड में प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार होता है। लगभग सवा करोड़ की आबादी वाला यह राज्य हर साल औसतन सात करोड़ लोगों का कुशलता से प्रबंधन करता है, जो कि प्रदेश की उच्चकोटि की कानून व्यवस्था का प्रतीक है।

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में दुनियाभर के हजारों निवेशकों और प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। राज्य ने निवेश के लिए उनका उत्साह यह दर्शाता है कि उत्तराखण्ड में बेहतर व्यावसायिक वातावरण, अच्छी कानून व्यवस्था, निवेश अनुकूल एवं सरल नीतियां, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकल्प रहित संकल्प है। ऐसी ही अनगिनत सुविधाएं और व्यवस्थाएं निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा दे रही हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आगे बढ़ता उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देश व
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में
डबल इंजन सरकार में उत्तराखण्ड
विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।

संकल्प
नये उत्तराखण्ड का

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

सपनों का साकार करती उत्तराखण्ड सरकार

• राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार-भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक गतव्य के रूप में तथा पर्यटन के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2022 में पुरस्कृत किया गया।

• श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत प्रथम चरण में ₹225 करोड़ के कार्य पूर्ण कराये गये है तथा वर्तमान में दूसरे चरण में ₹198 करोड़ के निर्माण कार्य एवं तीर्थ यात्रियों हेतु आवासीय सुविधाऐं विकसित किये जाने हेतु ₹190 करोड़ के कार्य गतिमान है। जिनका वर्ष 2024 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

• वर्ष 2023 चार धाम यात्रा के दौरान 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं / यात्रियों द्वारा चार धाम के दर्शन किये गये हैं।

• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम को Smart Spiritual Hill Town के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चरणवद्ध रूप से कार्य किये जा रहे है। भारत सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से ₹273 करोड के कार्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के अंतर्गत कराये जा रहे हैं। इन कार्यों में घाट निर्माण, रेन सेल्टर, टूरिस्ट इन्टरपिटेशन सेन्टर आदि अवस्थापना सुविधाओं के कार्य किये जा रहे है। उक्त के अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों हेतु आवासीय सुविधाऐं विकसित किये जाने हेतु ₹40 करोड के कार्य सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत गतिमान है।

• गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तथा सोनप्रयाग-केदारनाथ तक रोपवे का निर्माण कार्य आगामी वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य।

• नंदा गौरा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार की 02 बालिकाओं को दो किश्तो क्रमशः जन्म के समय ₹11000 एवं बालिका द्वारा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर ₹51000 की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में योजनान्तर्गत अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया गतिमान है।

• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार, शारीरिक विकास, स्कूल पूर्व बच्चों (3 वर्ष से 06 वर्ष) को आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केले चिप्स योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 03 फरवरी, 2024

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

आगे बढ़ता उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देश व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।

सपनों का साकार करती उत्तराखण्ड सरकार

- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के द्वारा राज्य में आंगनवाडी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती/धात्री महिलाओं में एनीमिया एवं मृत्यु व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है।

- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम गर्भवती महिला को प्रसव के समय प्रसूता एवं नवजात शिशु को आवश्यक सामग्री युक्त किट उपलब्ध करवायी जाती है। वर्तमान में इस योजना का लाभ एक परिवार की दो बालिका के जन्म पर दिया जा रहा है। प्रथम बालक के जन्म पर योजना से लाभान्वित करने कर प्रस्ताव किया गया है।

- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त आंगनवाडी केंद्रों में आने वाले स्कूल पूर्व बच्चे शिक्षा के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ में सुधार के साथ-साथ कुपोषण दर कम करना तथा आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि किये जाने के उददेश्य से यह योजना राज्य में प्रारम्भ की गई। सप्ताह में 04 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को 03 से 06 वर्ष के बच्चों को फोर्टिफाइड विटामिन ए वी डी युक्त सुगन्धित दूध दिया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में एस.जी.एस.टी. के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य का कुल संग्रह ₹7341 करोड़ रहा है, जो गत वित्तीय वर्ष 2021-22 मे प्राप्त संग्रह ₹5973 करोड़ के सापेक्ष लगभग 23 प्रतिशत अधिक था।

- गोट वैली परियोजना (Goat Valley) के अंतर्गत पशुपालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, सहकारिता विभाग व राज्य में बकरी विकास आधारित परियोजना का अभिसरण कर कलस्टर आधारित बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाना है। एक वैली के अन्तर्गत न्यूनतम् 100 लाभार्थीयो को लाभान्वित किया जाना है।

- पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन को वर्षभर मौसमी / बहुवर्षीय चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मा0 मंत्री मण्डल द्वारा आगामी पांच वर्षो हेतु उत्तराखण्ड चारा नीति को मंजूरी दी गई है।

- राज्य में मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गई है। जिसका उद्देश्य दालचीनी एवं तिमरू को वैकल्पिक नकदी फसल के रूप में प्रसारित करना है।

- काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में ऐरोमा पार्क की स्थापना।

- ऐरोमा वैली से राज्य के विभिन्न जनपदों में फसल आधारित 06 एरोमा वैलियों के माध्यम से 14,000 है। भूमि को सगन्ध फसलों से आच्छादित करने की योजना है। इससे कुल 37,800 कृषक लाभान्वित होंगे व 70,000 रोजगार सृजित होंगे।

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सेवा रेटिंग में यूपीसीएल हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

RO2024012521632

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in UttarakhandDIPR DIPR_UK UttarakhandDIPR

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

संकल्प
नये उत्तराखण्ड का

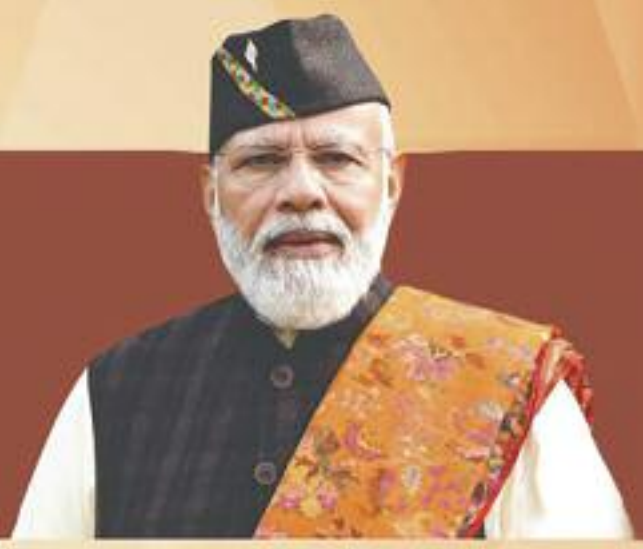

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

आगे बढ़ता उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देश व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल मे माह सितम्बर 2023 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा 1275 किमी मार्गों का नवनिर्माण, 2063 किमी0 लम्बाई में पुनः निर्माण तथा 58 नए सेतुओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 227 ग्रामों को सड़क यातायात से जोड़ा गया। पूर्व निर्मित पक्के मोटर मार्गों में कुल 3047 किमी मार्गों का नवीनीकरण कार्य किया गया।
- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत लक्ष्मणझूला सेतु के समीप 132.30 मीटर स्पान के वैकल्पिक सेतु (बजरंग सेतु) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- ऑल वेदर रोड़ परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 737 कि.मी. लम्बाई के विरुद्ध 671 कि.मी. लम्बाई में कार्य गतिमान है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 597 कि.मी. लम्बाई में 02 लेन चौड़ीकरण एवं 574 कि.मी. लम्बाई में सतह लेपन के कार्य पूर्ण किये जा चुके है, शेष कार्य प्रगति पर है। चारधाम परियोजना के अन्तर्गत कुल प्रदत्त स्वीकृति लागत ₹9399.45 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान अवधि तक कुल ₹6810.49 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित 975 अमृत सरोवरों के लक्ष्य के सापेक्ष 1239 सरोवरों को पूर्ण किया गया है जो 127% है।
- लखपति दीदी योजना। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये विजन 2025 तक स्वयं सहायता समूह की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जायेगा। इसी क्रम में यू.एस.आर.एल.एम द्वारा समूहों की 40270 सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में लखपति दीदी के रूप में तैयार किया है व वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50000 दीदीयों को लखपति दीदी के रूप में तैयार किये जाने का लक्ष्य है जिसकी प्रक्रिया गतिमान है।
- महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अन्तर्गत रक्षा बन्धन के सुअवसर पर महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु राज्य में 337 स्टाल लगाकर सामग्री का विपणन कराया गया। जिससे महिलाओं द्वारा ₹57.16 लाख की सामग्री विपणन कर अपनी आजीविका में वृद्धि की गयी।
- वाईब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम - इस महत्वकांक्षी योजना के तहत उत्तराखण्ड के तीन सीमान्त जनपद क्रमशः उत्तराकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के कुल 05 विकासखण्डों के 51 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। इसके अन्तर्गत समस्त चिन्हित गांवों की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। जिसमें एक ओर सभी गाँव को मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करने की प्राथमिकता दी गयी है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन सुविधाओं का विकास, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सतत आजीविका कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से लगभग ₹755 करोड़ से अधिक लागत की 500 से अधिक योजनाओं को प्रस्तावित कर इन गाँवों में वाईब्रेन्सी लाते हुए अधिकाधिक परिवारों को बसाया जायेगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in UttarakhandDIPR DIPR_UK UttarakhandDIPR

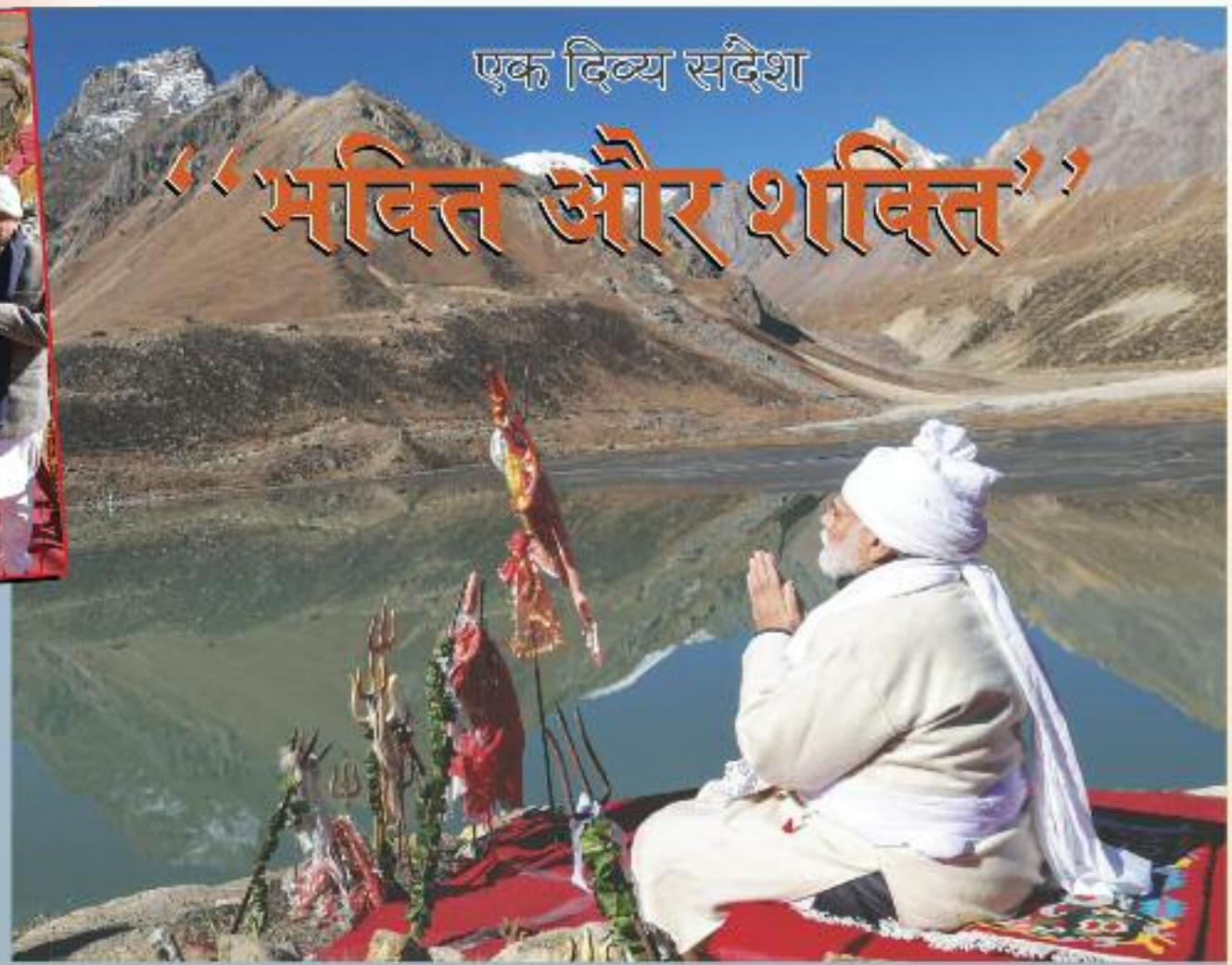

एक दिव्य संदेश

"भक्ति और शक्ति"

"मैंने प्रत्येक भारतीय के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत की मजबूती का संकल्प लेते हुए प्रार्थना की। मैंने आशीर्वाद मांगा कि उत्तराखण्ड के लोगों की सभी आकांक्षाएं पूरी हों।"

–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

- आदि कैलाश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री।
- प्रधानमंत्री के भ्रमण से आदि कैलाश क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
- स्थानीय लोगों में दिखा अभूतपूर्व उत्साह, कैलाश आगमन पर किया जोरदार स्वागत।

- गुंजी गांव में दूर-दराज से पहुंचे लोग, प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे।
- गुंजी में सेना के जवानों से बातचीत कर प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया।
- लोग पारम्परिक वेशभूषा में रहे मौजूद।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर स्वयं ढोल-दमाऊं भी बजाया।

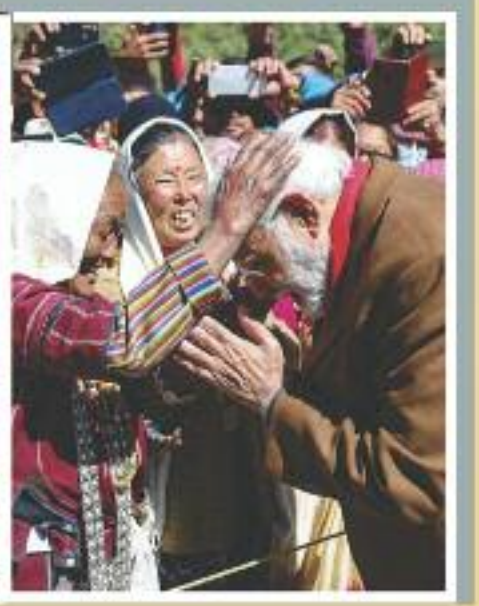

"केदारखंड संवारा अब मानसखंड की बारी"

"जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक भ्रमण से न केवल इन पवित्र स्थलों को नई पहचान मिली है, बल्कि स्थानीय लोगों को समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।"

"जब भी मैं आपके बीच उत्तराखण्ड में होता हूं, हमेशा खुद को धन्य समझता हूं।"

—नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

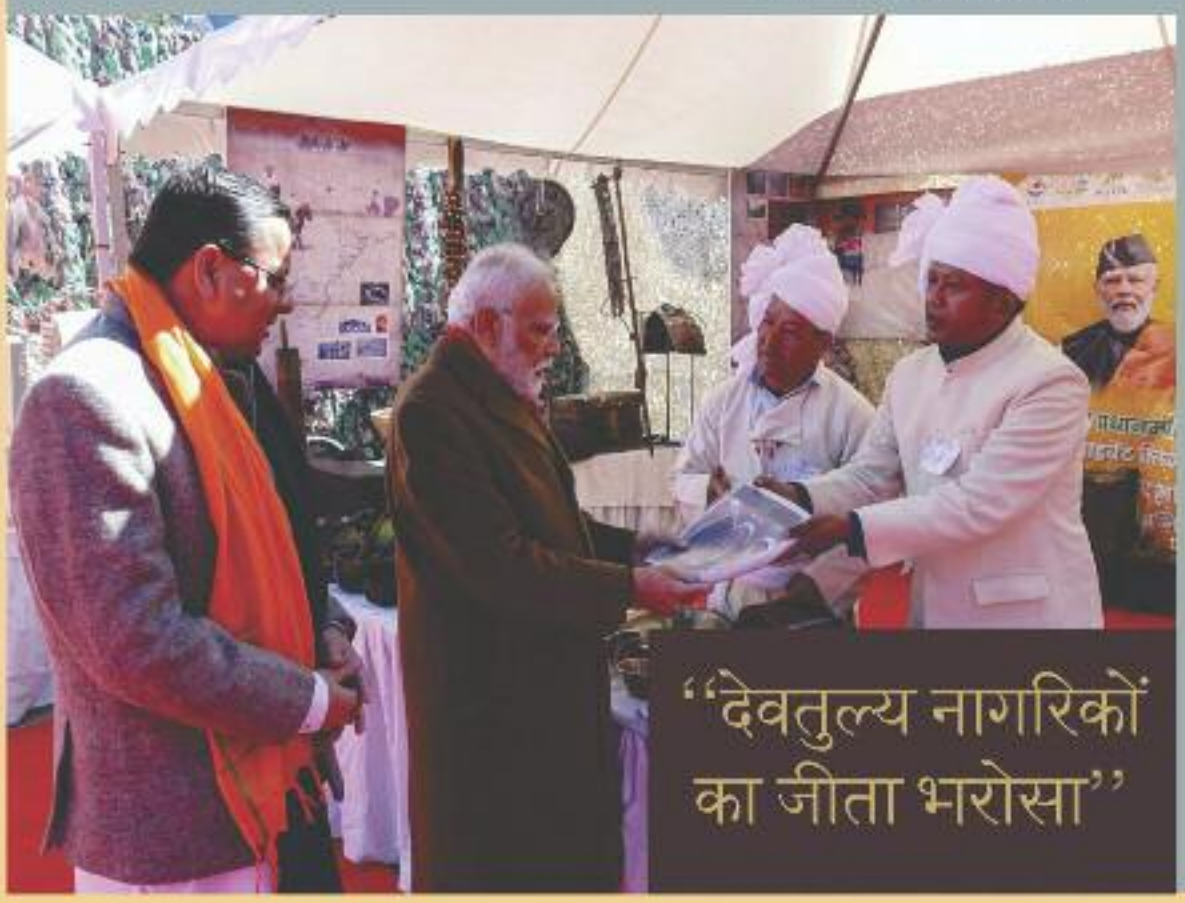

"देवतुल्य नागरिकों का जीता भरोसा"

मानसखंड मंदिरमाला मिशन के विजन पर लगाई मुहर

- मानसखंड के पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान।
- तीर्थाटन, पर्यटन और अध्यात्म के खुले द्वार।
- मानसखंड मंदिर माला मिशन को मिलेगी वैश्विक पहचान।
- ऐतिहासिक भ्रमण से स्थानीय लोगों की समृद्धि का मार्ग भी हुआ प्रशस्त।
- जागेश्वर धाम तीर्थाटन को मिलेगी गति।

''ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम''

"यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है और यह उनकी आवाज अधिक प्रभावी तरीके से सुना जाना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक कदम है।"

—नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

- देश में मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में यह सराहनीय कदम है।
- राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है।
- लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया।

''नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति आभार''

देवभूमि उत्तराखण्ड में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन होना सौभाग्य का विषय है।

G20 भारत 2023 INDIA

स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने का रोडमैप तैयार

- भारत लॉन्च करेगा वन हेल्थ मिशन – प्रो. अजय सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (भारत सरकार)।
- लगातार निगरानी से कम होगा महामारी का खतरा।
- मानव, पशु और वाइल्ड लाइफ की सर्विलांसिंग बढ़ाने पर बनी सहमति।
- ओपन एक्सिस की परेशानी होगी दूर – लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना और बचाव के उपायों से जागरूकता पर रहेगा फोकस।
- कॉमन प्लेटफार्म बनाकर करना होगा काम।
- जनजातियों के परम्परागत ज्ञान को आधुनिकता से जोड़ने पर होगा कार्य।

जी-20 सम्मेलन

"इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप सम्मेलन"

G-20 की थीम One Earth, One Family, One Future भारतीय संस्कृति की 'वसुधैव कुटुंबकम्' की सोच पर आधारित है। हमारे देश की प्राचीन और महान संस्कृति ने ही सर्वप्रथम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात 'समस्त विश्व एक परिवार है' की अवधारणा समस्त विश्व के समक्ष रखी थी। G-20 की यह विशेष बैठक हमारी सनातन संस्कृति की इसी मूल अवधारणा को पुष्पित व पल्लवित करने में सहायक सिद्ध होगी।

"जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, तब उत्तराखण्ड के नागरिक गौरवान्वित महसूस करते हैं।"

—नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

G-20 की बैठकों से उत्तराखण्ड को मिली "ग्लोबल पहचान"

- कल के शहरों का वित्तपोषण : समावेशी, लचीला और टिकाऊ सिद्धांत के तहत दो कार्यधाराओं पर चर्चा हुई।
- कार्य क्षेत्रों में सार्थक प्रगति हासिल करने के लिए प्रेसीडेंसी के प्रयासों को स्वीकार किया।
- प्रौद्योगिकी, इन्फ्राटेक और डिजिटलीकरण की भूमिका की खोज के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से लेकर बुनियादी ढांचे के लचीलेपन और तेज शहरीकरण और समावेशन पर चर्चा हुई।

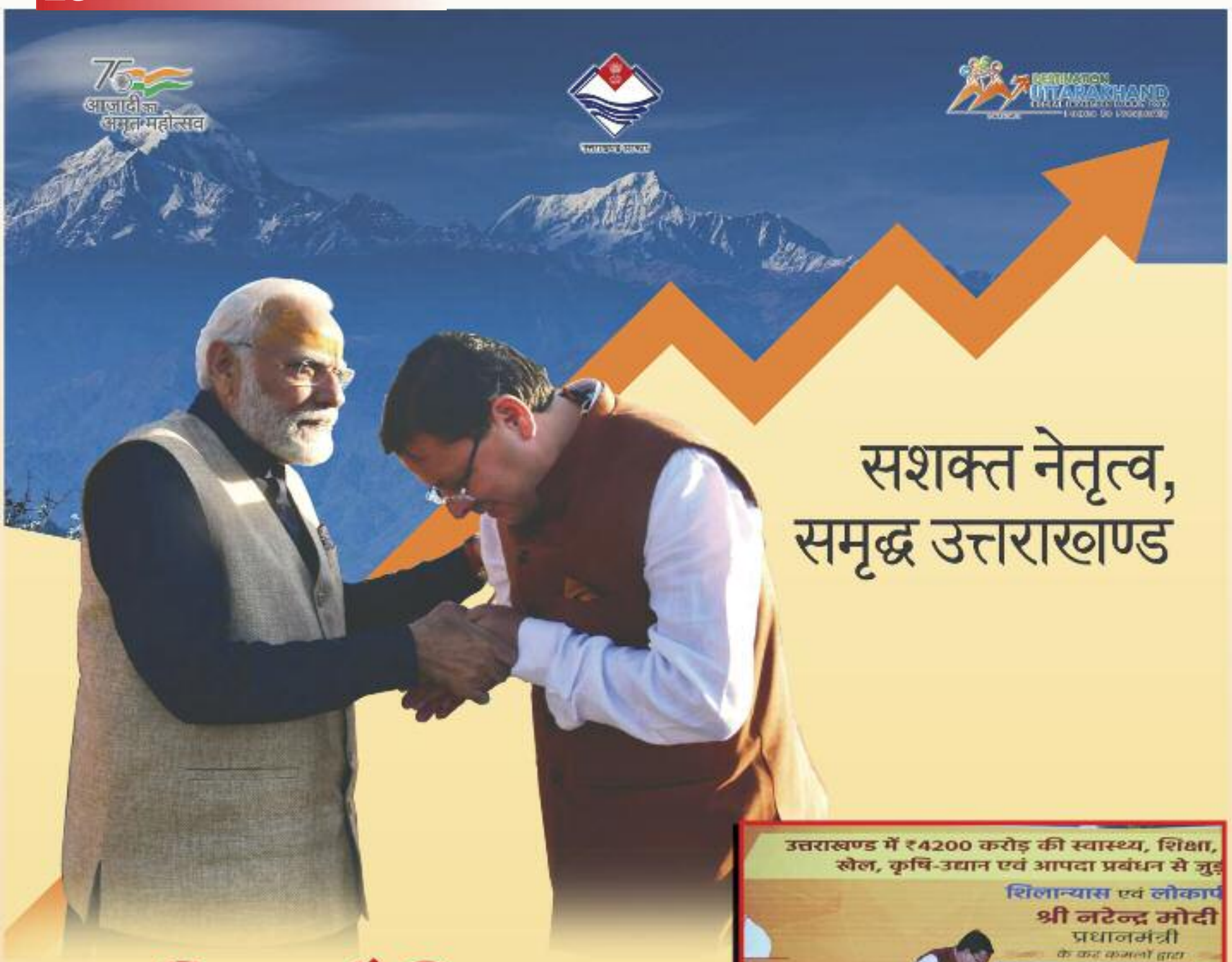

"विकास में विश्वास"

प्रधानमंत्री ने उत्तराखण्ड को लगभग ₹ 4 हजार 200 करोड़ की दी सौगात

21 हजार 398 पॉलीहाउस निर्माण, उच्च घनत्व वाले सघन सेब बागानों की योजना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 लेन एवं ढलान उपचार के 5 कार्य, राज्य में 32 पुलों का निर्माण, एसडीआरएफ के तहत अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और बचाव उपकरणों को मजबूत करना, देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का अपग्रेडेशन, बलियानाला, जनपद नैनीताल में भूस्खलन की रोकथाम हेतु उपचार, 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में हॉस्टल और कम्प्यूटर लैब का निर्माण, सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 100 बिस्तरों वाला उप जिला अस्पताल, चंपावत में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल ब्लॉक का निर्माण, रुद्रपुर में वेलो-ड्रोम निर्माण कार्य, स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान का निर्माण, चार धाम की भांति मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों का विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम, हाट कालिका एवं नैना देवी मंदिर में अवस्थापना सुविधाओं का विकास सम्बन्धित कार्यों का किया गया शिलान्यास।

पीएमजीएसवाई के तहत 76 सड़कें, पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 पुल, 09 जिलों में 15 ब्लॉक कार्यालय भवन, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 03 सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य, कौसानी बागेश्वर रोड, धारी- डोबा गिरेचिना रोड, नगला - किच्छा एस एच रोड डबल लेन, राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन एवं सुदृढ़ीकरण करने का कार्य, एन एच 309 बी-अल्मोड़ा- पेट्साल -पनुआनौला - दन्या एन एच टनकपुर चल्थी, प्रदेश में 39 पुल एवं देहरादून में यूएसडीएमए भवन, 38 ग्रामीण पंपिंग पेयजल योजनाएं और 03 ट्यूबवेल आधारित पेयजल योजनाएं, 419 ग्रामीण ग्रेविटी पेयजल योजनाएं, थरकोट, पिथौरागढ़ में कृत्रिम झील, 132 केवी पिथौरागढ़-लोहाघाट-चंपावत ट्रांसमिशन लाइन के कार्यों का किया गया लोकार्पण।

''ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तराखण्ड''

- देहरादून में दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन।
- ITC ने ₹ 5000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया।
- महिन्द्रा हॉलीडेज एण्ड रिसॉर्ट इण्डिया लिमिटेड के साथ ₹ 1000 करोड़ और ई-कुबेर के साथ ₹ 1600 करोड़ के निवेश का एमओयू किया गया।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹ 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य ।
- लंदन, दुबई के बाद अब सिंगापुर, ताइवान में आयोजित किए गए इंटरनेशनल रोड शो ।
- संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन एवं दिल्ली में कुल मिलाकर अब तक ₹ 54550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं जिसमें यूएई में ₹ 15475 करोड़, ब्रिटेन में ₹ 12500 करोड़ एवं दिल्ली में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में ₹ 26,575 करोड़ के एमओयू (4 सितंबर को ₹ 7600 करोड़ एवं 4 अक्टूबर को दिल्ली रोड शो के दौरान ₹18975 हजार करोड़) किए जा चुके हैं।
- 6 रोड शो, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बैंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद में आयोजित । निवेशक सम्मेलन के माध्यम से कम से कम ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया।
- 'पीस टू प्रोसपेरिटी' की टैगलाइन पर दिसंबर में उत्तराखण्ड में आयोजित हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ।

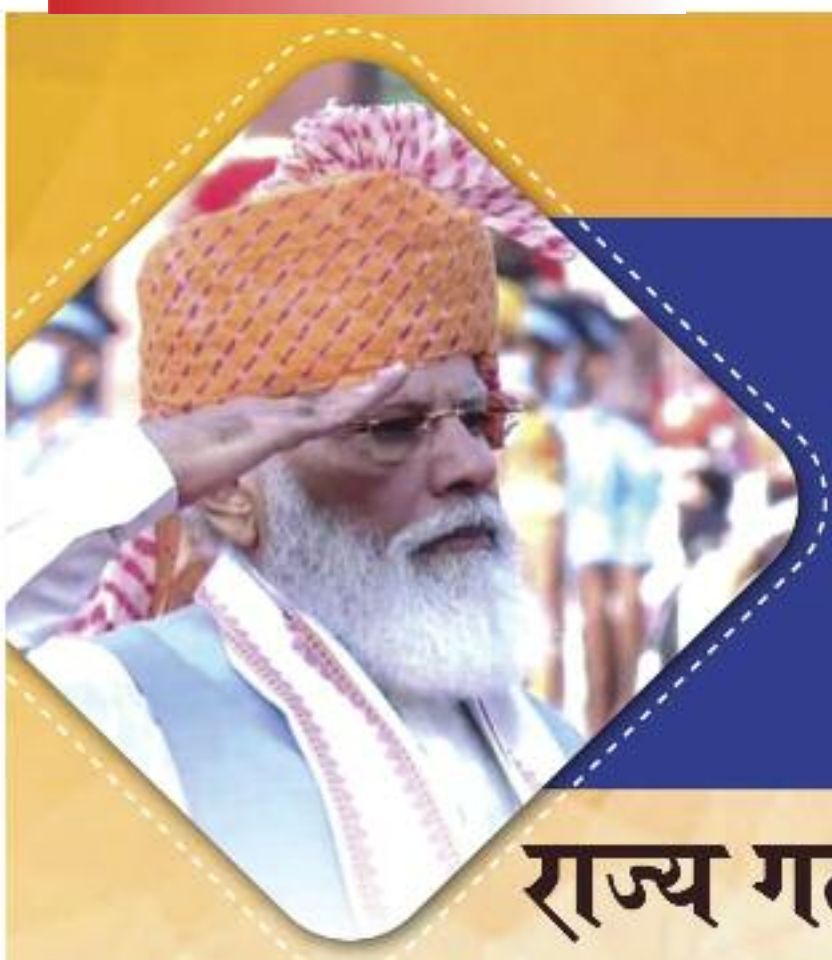

ऐतिहासिक पहल
न भूतो न भविष्यति।।

राज्य गठन रजत जयंती वर्ष 2025
सशक्त उत्तराखण्ड @25

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

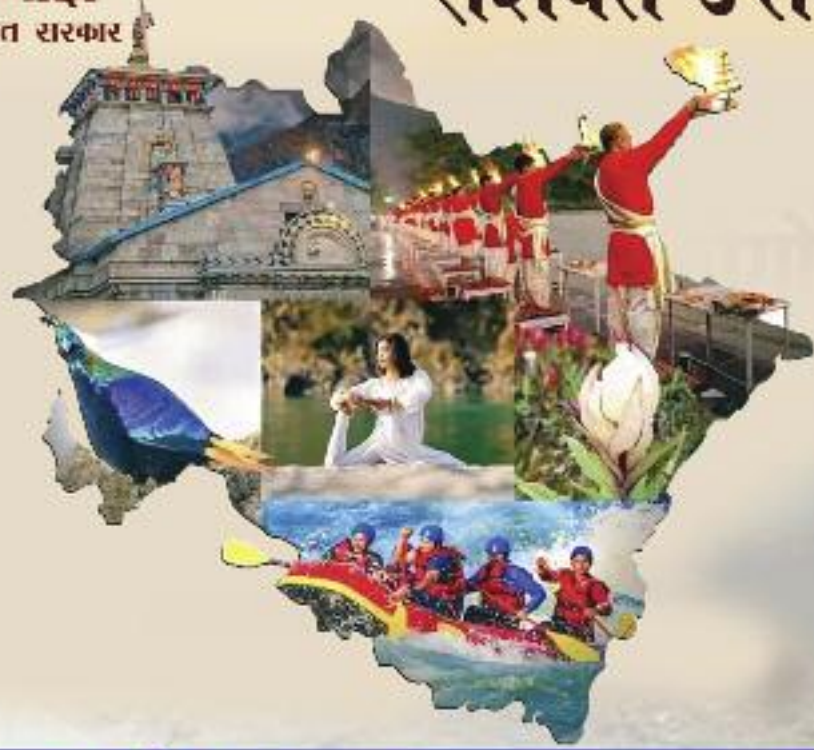

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विकास के 5 सशक्त स्तम्भ

- इकोलॉजी
- इकोनॉमी
- टेक्नोलॉजी
- एकाउंटेबिलिटी
- सस्टेनेबिलिटी

- राज्य विकास के लिए आगामी 10 सालों का रोड मैप तैयार।
- राज्य की जीएसडीपी 25 प्रतिशत बढ़ी।
- राजस्व दोगुना बढ़ाने की दिशा में हो रहा है कार्य।
- सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और सन्तुष्टि की नीति पर चल रही है सरकार।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब बालक होने पर भी मिलेगा किट का लाभ।
- UPSC, NDA व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले युवाओं को ₹50 हजार की जगह ₹1 लाख की मिलेगी धनराशि।
- ITDA के ढांचे में स्वीकृत कतिपय पदों के सृजन के संबंध में निर्णय।
- अब औद्योगिक क्षेत्रों के नक्शों को पास करेगा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA)।
- प्रदेश सरकार द्वारा 35 नई पशु चिकित्सा मोबाइल वैन खरीदी जाएंगी।
- राजस्व क्षेत्रों में बने 6 नए थानों एवं 21 पुलिस चौकियों हेतु होगी 327 नए पदों पर भर्ती।
- परिवहन निगम में 195 मृतक आश्रितों के पदों पर लगी रोक को हटाया गया।
- कर्मचारियों की बीमा अथवा बचत योजना में संशोधन किया गया।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 स्टेशनों के आसपास के कस्बों को मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा विकसित।
- पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक किया जाएगा लागू।
- श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने की मंजूरी।
- अंत्योदय एवं बीपीएल कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर प्रतिमाह मिलेगा आयोडीन युक्त नमक।
- प्रदेश की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लिए जाने हेतु ₹400 करोड़ से अधिक की शासकीय प्रत्याभूति को दी मंजूरी।
- BKTC के विभिन्न सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती हेतु दी मंजूरी।
- कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने अथवा पृथक नगर निकाय बनाए जाने को दी सैद्धांतिक स्वीकृति।
- UIIDB द्वारा संचालित की जाएगी हरिद्वार एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना।
- वित्त विभाग के अन्तर्गत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया।
- राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से 25 संविदा सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती।
- राज्य में पुरानी नजूल नीति यथावत रहेगी प्रभावी।

स्वर्णिम उपलब्धियों से परिपूर्ण वर्ष 2023

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के तहत ₹3.5 लाख करोड़ के निवेश MoU साइन

चारधाम यात्रा ने स्थापित किया नया कीर्तिमान
56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से भी अधिक
श्रद्धालु गंगाजल लेने हेतु उत्तराखण्ड पधारे

PMGSY
के तहत राज्य में
104 सड़कों
के निर्माण हेतु
₹856.84 करोड़
की धनराशि मंजूर

देवभूमि को मिली
वंदे भारत एक्सप्रेस
की सौगात,
दिल्ली-देहरादून
के बीच शुरु हुआ
संचालन

पर्यटन : ''स्थापित हुए नए आयाम''

RO2024012521632

आरीएनीआई नी : UTTHIN/2009/29438, उत्तर प्रदेश : UP/GBDA58/2014-16